जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 230 प्रभात जालोर, गुरूवार, 27 नवम्बर, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'जब अलावेरु ने सभी निर्णय लिए बिहार में, तो वो हार की जिम्मेवारी भी लें'

अन्ततोगत्वा कांग्रेस ने हार स्वीकार की बिहार में और शुक्रवार को हार का विश्लेषण करने के लिए उच्चस्तरीय बैठक रखी है दिल्ली में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवंबर। कांग्रेस को आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ा है कि वह बिहार चुनाव हार गई है। गुरुवार 27 जनवरी को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और बिहार कांग्रेस इकाई बैठक करेंगे और बिहार में मिली जबरदस्त पराजय पर मंथन करेंगे। बिहार में कांग्रेस ने 61 में से केवल 6 सीटें जीतीं हैं।

नई दिल्ली से पटना तक सभी हथियार अब बाहर आ चुके हैं, क्योंकि यह अपेक्षित है कि वरिष्ठ नेता और नई टीम, जो राहुल गांधी के संरक्षण में आकर पार्टी चला रही है, के बीच करारी भिड़ंत में कोई कसर नहीं रहेगी।

संकट के केन्द्र में कृष्णा अलावेरु हैं, जो एआईसीसी के बिहार प्रभारी थे और जिन्होंने अपनी टीम के साथ सभी फैसले लिए, चाहे कोई भी कुछ कहे।

- बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने अपने-अपने चाकू-छुरी तैयार कर रखे हैं, राहुल की युवा टीम की सर्जरी के लिए।
- फ्री व फ्रैंक मंथन करने देने का वादा किया गया है। अतः पूरा घमासान होने की संभावना है, बैठक में।
- अलावेरु का रवैया यह तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि वे अगली पीढ़ी के लिए टीम तैयार कर रहे हैं, पर, उनके इस तर्क को कोई स्वीकार करता नहीं दिख रहा है।
- एक अन्य ग्रुप यह तर्क दे रहा है कि पार्टी को आरजेडी (तेजस्वी यादव) के चंगुल से मुक्ति लेकर, अपने ही दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी ने सभी हथकंडे अपनाये थे, कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने के लिए।
- अगर, बैठक में "फ्री व फ्रैंक" बातचीत का मौका नहीं दिया गया तो कांग्रेस का सूरज डूबता सा लग रहा है।

वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अगर अलावेरु और उनकी टीम ने बिना किसी से सलाह-मशवरे के सारे फैसले किए, तो उन्हें नतीजों की पूरी जिम्मेदारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विद्याधर नगर में पैंथर ने बछड़े का शिकार किया

जयपुर, 26 नवम्बर। जंगल में खाना -पीना नहीं मिलने के कारण अब जंगली जानवरों का मूवमेंट रिहायशी इलाकों में आए दिन नजर आ रहा है। वीवीआईपी इलाके में लैपर्ड के मूवमेंट के बाद, शास्त्री नगर व विद्याधर नगर इलाके में मंगलवार देर रात दो बजे लैपर्ड के होने की सूचना मिली। तुरंत ही यह सूचना पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई और इलाके में दहशत व्याप्त हो गई।

सेक्टर -10 शिव मंदिर के पुजारी सुधांशु ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब दो बजे कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज आई। काफी देर तक कुत्तों के भौंकने पर बाहर जाकर देखा तो सब कुछ ठीक लगा। लेकिन बुधवार सुबह मंदिर-परिसर में स्थित बगीचे में एक बछड़ा मरा हुआ मिला। बगीचे में घास के आसपास लैपर्ड के पद- चिन्ह भी दिखाई दिए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरु किया। इसके बाद बुधवार दोपहर पानी पेच इलाके में लैपर्ड का मूवमेंट दिखाई दिया।

- वन विभाग की टीम के प्रयासों के बाद भी पैंथर अभी पकड़ा नहीं गया।

रिहायशी इलाकों में पहले भी लैपर्ड का कई बार मूवमेंट देखा जा चुका है। सिविल लाइंस, विद्याधर नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जयसिंह पुरा, जगतपुरा,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में स्पीकर की पोस्ट पर भाजपा से सीधी टक्कर ली जद (यू) ने

गृह मंत्रालय पद गंवाने के बाद अपनी ताकत दिखाने के लिए जद (यू) ने यह रणनीति अपनाई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। नव-निर्वाचित बिहार विधानसभा का पहला सत्र, जो 1 दिसम्बर को शुरू होना है, अब गठबंधन पार्टनर, भाजपा और जदयू के बीच एक ताजा टकराव के वातावरण में शुरू होने वाला है, क्योंकि दोनों दल स्पीकर के महत्वपूर्ण पद को लेकर गतिरोध में फंसे हुए हैं।

यह गतिरोध तब और बढ़ गया, जब जदयू ने, अपनी पसंद के रुप में, वरिष्ठ नेता और चार बार के विधायक दामोदर रावत का नाम स्पीकर के लिए प्रस्तावित किया। जदयू का यह कदम भाजपा की पहले की उस घोषणा से सीधे तौर पर टकरा रहा है, जिसमें पार्टी ने अपने अनुभवी दलित नेता और आठ बार के विधायक प्रेम कुमार को स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था।

दोनों पार्टियों के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। बातचीत में शामिल नेता यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह मुद्दा गठबंधन में विश्वास की बढ़ती कमी का द्योतक बन गया है।

- भाजपा ने पार्टी के 8 बार के विधायक एवं अनुभवी दलित नेता प्रेम कुमार का नाम स्पीकर के पद के लिए पहले ही दे दिया था। पर, अब जद (यू) ने अचानक से अपने चार बार के विधायक दामोदर रावत का नाम आगे कर दिया है।
- इससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है।
- अब सवाल यह है कि एक दिसंबर से नई विधानसभा का सत्र क्या सत्तारूढ़ गठबंधन, एनडीए की दरारों के साए में होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तनाव सरकार के गठन के शीघ्र बाद तभी शुरु हो गया था, जब गृह मंत्रालय, जिसे नीतीश कुमार ने लगभग दो दशकों तक संभाला था, भाजपा के पास चला गया था। जदयू के नेताओं ने इस कदम को भाजपा के दबदबे एवं प्रभुत्व की अप्रत्याशित पुष्टि के रूप में देखा, जबकि भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि यह पोर्टफोलियो वितरण नई गठबंधन व्यवस्था में "शक्ति समानता" को दर्शाता है।

अब, जब सत्र की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है, दोनों दल विधानसभा में टकराव से बचने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। बताया जाता है कि भाजपा और जदयू के वरिष्ठ नेता एक ऐसा फॉर्मूला तलाश रहे हैं, जिससे दोनों की साख बच जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कर्नाटक में नेतृत्व संकट है, सोनिया, राहुल और मैं इसे फिक्स कर देंगे'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में नेतृत्व संकट की बात स्वीकार की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवंबर। कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कर्नाटक के नेतृत्व-संकट के जगजाहिर घटनाक्रम को स्वीकार किया और जोर देकर कहा कि राज्य में पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार (डीकेएस) के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान का समाधान जल्द हो जाएगा।

पार्टी अध्यक्ष ने आज दोपहर बाद कहा, "सोनिया (गांधी), राहुल (गांधी), और मैं इसे सुलझा लेंगे, सूत्रों ने भी कहा कि 1 दिसंबर, जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तक इसका समाधान मिल जाएगा।

सूत्रों ने यह भी कहा कि खड़गे और राहुल गांधी की एक बैठक अगले 48 घंटों में होने की संभावना है, इसके बाद, संभवतः शुक्रवार को सिद्धारमैया और डीकेएस को दिल्ली बुलाया जाएगा।

- सूत्रों ने बताया कि अगले 48 घंटों में खड़गे व राहुल की मीटिंग होगी, फिर मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उन्हें चुनौती दे रहे डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया जाएगा।
- अब जाकर कांग्रेस ने औपचारिक रूप से माना है कि पार्टी शासित कर्नाटक में नेतृत्व संकट है। पार्टी की सरकार सिर्फ तीन राज्यों में है। इनमें से एक में सरकार पर संकट मंडरा रहा है।
- यह स्वीकारोक्ति एक सप्ताह पहले पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा किए गए इस दावे के विपरीत है कि पार्टी में सब ठीक है।

यह कि कांग्रेस ने अब इस सत्ता संघर्ष को उस राज्य में, जो उन तीन राज्यों में से एक है, जहाँ उसकी सत्ता है, और जहाँ अगले दो साल में चुनाव होने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी ने 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने '26/11' मुंबई आतंकवादी हमले में अपने प्राण गंवाने वाले नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों को बुधवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा।

- उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों व आम नागरिकों के साहस और बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा।

गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, मुंबई में 26/11 को हुए दुस्साहसी आतंकवादी हमले में अपने प्राण गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। भारत उनके साहस, बलिदान और शहादत को कभी नहीं भूलेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राबड़ी देवी को सरकारी बँगला खाली करने का नोटिस, आखिर क्यों?

अंदरूनी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने यह कदम भाजपा के दबाव में उठाया है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवंबर। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को दर्शाने वाले घटनाक्रम के अन्तर्गत, राज्य के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया है कि वे 10, सर्कुलर रोड वाला बँगला खाली करें। ज्ञातव्य है कि यह बँगला पिछले दस वर्षों से लालू परिवार की विभिन्न गतिविधियों का मुख्य केन्द्र रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री को अब इस विशाल बँगले के स्थान पर, 39 हार्डिंग रोड पर एक छोटा बँगला आवंटित किया गया है। नई सरकार का अप्रत्यक्ष संदेश साफ है: हालिया चुनाव में राजद की करारी हार के बाद, अब लालू परिवार को इतना बड़ा सरकारी बँगला, जो मुख्यमंत्री के आवास 1अणे मार्ग के ठीक सामने है, रखने का कोई हक नहीं है।

पटना हाई कोर्ट के 2019 के फैसले की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो राबड़ी देवी के पास बँगला खाली करने के अलावा शायद कोई विकल्प नहीं है। हालांकि राजद इस मुद्दे पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश में है और उसने दृढ़तापूर्वक कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूर्व मुख्यमंत्री बँगला खाली नहीं करेंगी। राजद की बिहार इकाई के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने एनडीए पर लालू प्रसाद यादव के प्रति मन में द्वेष रखने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री ने यह कदम "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा को खुश करने के लिए" उठाया है। उनकी यह सोच पूरी तरह निराधार भी नहीं लगती, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने कभी राबड़ी देवी को सर्कुलर रोड वाला बँगला खाली कराने की पहल नहीं की। ऐसी स्थिति में, यह प्रश्न उठता ही है कि यह कदम एकाएक अब क्यों?

- यह संकेत है कि भाजपा बिहार सरकार में अपना दबदबा कायम करना चाहती है।
- राबड़ी देवी का बँगला, 10 सर्कुलर रोड, गत दस साल से लालू परिवार का केन्द्र है। यह विशाल बँगला मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने है।
- सवाल यह है कि नीतीश तो इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, फिर बँगला खाली करने का नोटिस अब क्यों दिया गया, वो भी एकाएक, क्या इसके पीछे भाजपा का दबाव है।
- इस नोटिस का आधार पटना हाई कोर्ट के 19 फरवरी 2019 के फैसले को बताया गया है, जो तेजस्वी की याचिका पर आया था, तब तेजस्वी ने उपमुख्यमंत्री का बँगला खाली करने के नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका खारिज कर आदेश दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से बँगला, स्टाफ आदि सुविधाएँ वापस ली जाएं।

देश के अन्य हिस्सों की तरह सरकारी बँगले बिहार में भी राजनीतिक टकराव का प्रतीक रहे हैं। सन् 2015 में जब महागठबंधन सत्ता में आया और तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बने, तो वे 5 देशरत्न मार्ग के आलीशान रूप से नवीनीकृत बँगले में रहने लगे और उसे उपमुख्यमंत्री का स्थायी आवास घोषित करवाया। लेकिन 2017 के बाद, जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, तो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली विस्फोट के आरोपी उमर को पनाह देने वाला गिरफ्तार

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राजधानी में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट की वारदात को अंजाम देने वाले आतंकवादी उमर उन नबी को पनाह देने के आरोप में हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के धौज का रहने वाला शोएब इस मामले में गिरफ्तार होने वाला सातवां आरोपी है।

- एनआईए ने फरीदाबाद में रहने वाले शोएब को हिरासत में लिया।

एनआईए की जांच से पता चला है कि शोएब ने 10 नवंबर को कार बम धमाका होने से पहले उमर को रसद सहायता प्रदान की थी। इस धमाके में कई लोग मारे गये थे तथा कई अन्य घायल हुए थे। एनआईए ने जांच के तहत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप की लाज बचाने के लिए जरुरी है कि राष्ट्रपति ज़ैलेन्स्की वॉशिंगटन जाएं, शांति प्रस्ताव पर बातचीत करने

अन्यथा, ट्रंप की प्रतिष्ठा यह ही बनकर रह जाएगी कि वे बड़ी-बड़ी डींग मारते हैं, पर उनके बड़-बोलेपन का जमीन पर कुछ असर नहीं होता

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। डॉनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति के रुप में अपने कार्यकाल अवधि के सबसे कठिन दौर का सामना कर रहे हैं। राजनीतिक हालात लगातार उनके खिलाफ होते देख रहे हैं और जनता का विश्वास भी रिकॉर्ड स्तर तक गिरा है। हाल के हफ्तों में आए राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में यह साफ दिखा कि लोग उनकी कामकाज की शैली से असंतुष्ट हो रहे हैं। घरेलू तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और नीतियों को लेकर अस्पष्ट संदेशों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ट्रम्प, जो हमेशा राजनीति के नियमों को धता बताने पर गर्व करते थे, उनके लिए ये आंकड़े एक गंभीर चेतावनी हैं। फिर भी, इन मुश्किलों के बीच यूक्रेन-रूस शांति समझौते की दिशा में उनका बड़ा और सक्रिय प्रयास एक संभावित पोलिटिकल लाइफलाइन के रूप में उभरा है, ऐसा कदम, जो सफल होने पर देश और विदेश, दोनों जगह उनकी स्थिति मजबूत कर सकता है।

नवीनतम सर्वे के पैटर्न साफ दिखाते हैं कि अलग-अलग वर्गों में उनके समर्थन में गिरावट आ रही है। रिपब्लिकन रुझान वाले स्वतंत्र मतदाताओं का समर्थन भी कमज़ोर पड़ रहा है और उदारवादी वर्ग में उन पर संदेह बढ़ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि भले ही उनका पक्का वोटर वर्ग अभी भी उनके साथ है, लेकिन वह व्यापक समर्थन, जिसने उन्हें दोबारा सत्ता तक पहुंचाया था, अब अस्थिर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति के रूप में आंतरिक अस्थिरता की छवि उनके उस दावे को ढँकने लगी है, जिसमें वे खुद को रणनीतिक रूप से मजबूत नेता बताते रहे हैं।

- यह छवि, उनकी सरकार को ले डूबने के लिए काफी है।
- अतः, उनकी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि ज़ैलेन्स्की वॉशिंगटन जरुर आएं, अन्ततोगत्वा कोई "डील" (समझौता) हो या न हो, यूक्रेन-रूस युद्ध में।
- ट्रंप के लिए यह भी जरूरी है कि रूस भी शांति प्रस्ताव पर झूठी सच्ची "हामी" भरे। अतः ट्रंप भारी रूप से चिंताग्रस्त हैं, क्योंकि ट्रंप के वफादार समर्थकों के अलावा, छोटी-मोटी पार्टी वाले समर्थक, जो उनको सत्ता में बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, भी धीरे-धीरे खिसक रहे हैं।

इस स्थिति में, पूर्वी यूरोप में शांति के प्रयासों में अचानक आई तेजी का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। खबरें हैं कि यूक्रेन ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा कराए जा रहे शांति समझौते को "मूल रूप से स्वीकार" कर लिया है, भले ही अभी सहमति पक्की नहीं हुई हो, लेकिन यह वाइट हाउस को राष्ट्रीय चर्चा को नया रुप देने का मौका देती है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने सी.बी.एस. न्यूज को बताया कि कीव ने अमेरिकी ढांचे के मुख्य बिंदुओं को मान लिया है और कुछ "छोटी बातें" तय होना बाकी हैं। अगर दुनिया के सबसे जटिल और लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों में अमेरिका कोई ठोस प्रगति कराता है, तो ट्रम्प खुद को एक बड़े राजनयिक नेता के रूप में पेश कर सकते हैं, खासकर ऐसे समय में, जब उनकी घरेलू छवि कमज़ोर पड़ रही है।

ट्रम्प के सलाहकार इस बात को भली-भांति समझते हैं। एक सफल शांति समझौता, या कम से कम उसकी दिशा में मजबूत प्रगति, गिरते पोल नंबरों का मुकाबला कर सकती है। इससे उनके उस लंबे समय से किए जा रहे दावे को भी बल मिलेगा कि एक वही हैं, जो ऐसी "डील" "करा सकते हैं," जो औरों से नहीं हो पाए। रिपब्लिकन पार्टी में उनके समर्थक अभी से ही उनकी सक्रिय कूटनीति की तुलना पिछली सरकारों की कथित रुकावट से कर रहे हैं। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की इस महीने अमेरिका आते हैं और समझौते को आधिकारिक रूप देते हैं, तो सिर्फ इससे बनने वाली छवि से ही वाइट हाउस को एक दुर्लभ राजनीतिक जीत मिल सकती है।

लेकिन यह प्रयास बेहद जटिल भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारतीय संविधान का 9 भाषाओं में अनुवाद जारी किया

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। हर साल 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। यह वह ऐतिहासिक दिन है, जब साल 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। इसके कुछ अनुछेद 26 नवंबर को लागू कर दिए गए थे। हालाकि, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ, जिसके बाद भारत एक गणराज्य बना। इस साल 2025 में 76वें संविधान दिवस को खास बनाने के लिए केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है।

- इससे देश के नागरिकों को अपनी भाषा में संविधान को पढ़ने व समझने का मौका मिलेगा।

सरकार द्वारा इस साल संविधान के नौ भारतीय भाषाओं में अनुवाद जारी किये गये। यह पहल देश के नागरिकों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

राजस्थान में अनियोजित शहरीकरण: एक नई चुनौती

राजस्थान की धरती सदियों से अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक विविधता के लिए जानी जाती रही है। मरुस्थल की सादगी और राजमहलों की भव्यता के बीच संतुलित यह प्रदेश अब तेजी से बदल रहा है। विकास की नई परिभाषाएँ यहाँ की जीवनशैली, जनसंख्या के वितरण और पर्यावरणीय ताने-बाने को पुनर्गठित कर रही हैं। पिछले दो दशकों में शहरी विस्तार की जो रफ्तार राजस्थान के शहरों में देखी गई है, वह अभूतपूर्व है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और अलवर जैसे शहर अब छोटे नगरों और गाँवों को अपने भीतर समेटते जा रहे हैं। यह परिवर्तन विकास और रोजगार के अवसर तो ला रहा है, किंतु इसके पीछे छिपे खतरे भी कम नहीं हैं।

राजस्थान परंपरागत रूप से कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य रहा है। ठामीण आबादी यहाँ की रीढ़ रही है, और गाँवों की सामाजिक संरचना से ही इस प्रदेश का सांस्कृतिक स्वर आकार लेता रहा है। लेकिन पिछले पंद्रह-बीस वर्षों में शहरीकरण की गति इतनी तेज हुई है कि ग्रामीण जीवन अब शहर की परिधि में सिमटता जा रहा है। नई औद्योगिक परियोजनाएँ, रियल एस्टेट की बढ़ती माँग, और पर्यटन क्षेत्र का विस्तार ने ग्रामीण भूमि को निगलना शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप, खेती की जमीनें सिमट रही हैं, और पारंपरिक व्यवसाय भी शहरों पर निर्भर होते जा रहे हैं।

शहरीकरण अपने आप में नकारात्मक नहीं है, लेकिन जब यह अनियोजित और अति-केंद्रित हो जाए, तो कई गंभीर समस्याएँ जन्म लेती हैं। जयपुर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कभी राजसी सौंदर्य, गुलाबी आभा और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध यह शहर आज यातायात जाम, प्रदूषण, पानी की कमी और बढ़ती जनसंख्या दबाव से जूझ रहा है। जोधपुर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक शहरों में भी इसी प्रवृत्ति के लक्षण दिखने लगे हैं। नगर सीमा के बाहर बसे गाँव अब 'स्मार्ट सिटी' की परिधि में आ रहे हैं, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का टकराव स्पष्ट दिखाई देता है। शहरों का फैलाव केवल भौगोलिक नहीं, सामाजिक रूप से भी हो रहा है-लोगों के जीवन-मूल्य, रिश्तों के स्वरूप और जीवन की गति में व्यापक परिवर्तन दिख रहा है।

अति-शहरीकरण का सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। मरुस्थल राज्य होने के नाते राजस्थान सदैव जल संकट से जूझता रहा है। नलकूपों की अंधाधुंध खुदाई, हरियाली के नाम पर अकल्पनीय निर्माण, और भूगर्भीय जल का अनियंत्रित दोहन अब भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी बन चुका है। जो शहर कभी जल-संवेदनशील थे, वे अब जल के उपभोग पर निर्भर हो गए हैं। जयपुर का उदाहरण लें तो आमेर और जलमहल जैसे तालाब जिनके जल पर कभी पूरा नगर बसता था, अब मात्र पर्यटन स्थल बनकर रह गए हैं। बढ़ते निर्माण कार्य और सड़क विस्तार के चलते वर्षा का पानी जमीन में समाने की बजाय नालों में बह जाता है। इससे भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है।

सामाजिक दृष्टि से देखें तो अति-शहरीकरण ने असमानता की खाई को चौड़ा किया है। शहरों में अमीरी और गरीबी के बीच की विभाजक रेखाएँ और गहरी हो रही हैं। एक ओर ऊँची इमारतों में रहने वाले लोगों का जीवन विलासिता से भरा है तो दूसरी ओर उन्हीं शहरों के छोर पर झुग्गी-झोपड़ियाँ बसती जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों से पलायन करने वाले लोग सस्ते श्रम के रूप में इन शहरों की रीढ़ तो बनते हैं, लेकिन उन्हें आधारभूत सुविधाएँ नहीं मिल पातीं। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी सुविधाएँ शहरों के केंद्र तक सीमित हो चुकी हैं।

राजस्थान के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। विकास आवश्यक है, लेकिन उसका स्वरूप लोक-जीवन के अनुकूल होना चाहिए। शहरों का विस्तार टिकाऊ तभी बन सकता है जब उसमें जल-संरक्षण, हरित क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था, और सांस्कृतिक विरासत का समन्वय हो। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ ताकि लोग केवल बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर भागने को विवश न हों। छोटे कस्बों को आत्मनिर्भर बनाकर ही बड़े शहरों पर दबाव कम किया जा सकता है।

अति-शहरीकरण का एक और गंभीर पहलू है सांस्कृतिक क्षरण। राजस्थान की पहचान उसकी लोकसंस्कृति, पोशाक, बोली, संगीत और सामुदायिक जीवन से रही है। लेकिन अब यह सांस्कृतिक धरोहर शहरों के विस्तार में खोती जा रही है। पीढ़ियों से चलने वाले पारंपरिक शिल्प और व्यवसाय अब आधुनिक बाज़ार व्यवस्था के दबाव में टिक नहीं पा रहे हैं। पारंपरिक मिट्टी के बर्तन, ब्लॉक प्रिंटिंग, कारीगरी या लोकगीतों की जगह अब फैक्ट्री-निर्मित उत्पादों और शो-कल्चर ने ले ली है। गाँव का 'मेला' अब मॉल में बदल गया है और सांझ का चबूतरा अब कैफे की टेबल बन गया है। इस बदलाव में सुविधा तो है, पर आत्मीयता नहीं।

राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी अति-शहरीकरण ने नई चुनौतियाँ दी हैं। नगर परिषदों और विकास प्राधिकरणों के पास इतनी तेज़ी से फैलते शहरों के लिए पर्याप्त योजना और संसाधन नहीं हैं। मास्टर प्लान अक्सर कागज़ों में ही सीमित रह जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य मनमाने ढंग से चलते रहते हैं। भूमि अधिग्रहण और अवैध कॉलोनियों का जाल व्यवस्थित शहरी विकास को बाधित कर रहा है। सरकार को अब ग्रामीण विकास की दिशा में पुनर्विचार करना होगा, ताकि गाँवों को इस शहरी दौड़ में पूरी तरह विस्थापित होने से बचाया जा सके।

अति-शहरीकरण के असर को शिक्षा और युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ भी चिंताजनक संकेत हैं। गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और अवसरों की तलाश में भेजते हैं, लेकिन शहरों की उपभोक्तावादी संस्कृति में उनकी जड़ें कमजोर होती जाती हैं। जीवन का अर्थ केवल आर्थिक उपलब्धियों से जोड़ा जाने लगा है। परिणामस्वरूप सामुदायिक भावना, पर्यावरणीय चेतना और आत्म-संतुलन जैसे मूल्य धीरे-धीरे मुरझा रहे हैं। परंपरा और आधुनिकता का यह असंतुलन आने वाले समय में सामाजिक विखंडन को जन्म दे सकता है।

राजस्थान के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। विकास आवश्यक है, लेकिन उसका स्वरूप लोक-जीवन के अनुकूल होना चाहिए। शहरों का विस्तार टिकाऊ तभी बन सकता है जब उसमें जल-संरक्षण, हरित क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था, और सांस्कृतिक विरासत का समन्वय हो। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ ताकि लोग केवल बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर भागने को विवश न हों। छोटे कस्बों को आत्मनिर्भर बनाकर ही बड़े शहरों पर दबाव कम किया जा सकता है।

राजस्थान का भावात्मक और सांस्कृतिक जीवन गाँवों से उपजा है। यदि अति-शहरीकरण की यह नीति इसी रफ्तार से चलती रही तो यह मूल पहचान खोने का खतरा बन सकती है। इस प्रदेश की आत्मा उसकी लोक-संस्कृति में है, जिसे शहरीकरण की चमक में मिटने नहीं देना चाहिए। विकास की दिशा ऐसी हो, जो परंपरा को नष्ट न करे, बल्कि उसे नए युग के साथ जोड़ दे। ऐसा संतुलित दृष्टिकोण ही राजस्थान को एक सशक्त, सुंदर और सतत भविष्य की राह पर ले जा सकता है।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

राशिफल गुरूवार 27 नवम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, सप्तम तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, धनिष्ठा नक्षत्र दिन 2:32 तक, ध्रुव योग दिन 12:09 तक, गर करण दिन 12:16 तक, चन्द्रमा आज दिन 2:07 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-मकर, मंगल-वृश्चिक, बुध-तुला, गुरू-कर्क, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज भद्रा रात्रि 11:30 से आरम्भ होगी। आज मित्र सप्तमी, नरसी मेहता जयन्ती है। पंचक दिन 2:07 से आरम्भ होंगे।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:18 तक, चर 10:56 से 12:14 तक, लाभ-अमृत 12:14 से 2:52 तक, शुभ 4:10 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:59, सूर्यास्त 5:29 तक

मेष

व्यावसायिक/आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

सिंह

विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

मकर

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

तुला

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कर्क

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

वृश्चिक

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

एसआईआर-2026: डिजिटल लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम और विरासत का संरक्षण

उत्सव कौशल

मतदाता सूची का शुद्धिकरण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अस्तित्व का दस्तावेज तैयार करने का महायज्ञ है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता है और उसकी सबसे बड़ी पूंजी मतदाता सूची की शुद्धता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 को यदि हम केवल नाम जोड़ने और हटाने की एक नियमित वार्षिक कवायद भर मानें तो यह इस अभियान के मूल उद्देश्य के साथ न्याय नहीं होगा। डीग जिले में इस अभियान के क्रियान्वयन के दौरान जो अनुभव सामने आए हैं, वे बताते हैं कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ प्रशासनिक दक्षता और जन-भागीदारी मिलकर डिजिटल लोकतंत्र की नींव रख रहे हैं।

अतीत से भविष्य का सेतु :- इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी नागरिकता, पहचान या वंशावली सिद्ध करने के लिए दशकों पुराने (जैसे वर्ष 2002 या पूर्व के) रेकार्ड खोजते हैं। एसआईआर 2026 आज उसी लिगेसी डेटा को वर्तमान डिजिटल इकोसिस्टम के साथ जोड़ने का काम कर रहा है।

मैंने कई बार ग्रामीण अंचलों में संवाद के दौरान यह बात दोहराई है कि आज भरा गया आपका एक गणना प्रपत्र केवल वोट देने का अधिकार पत्र नहीं है, बल्कि यह आने वाले 20-30 वर्षों बाद आपकी अगली पीढ़ी के लिए विरासत का प्रमाण बनेगा। जब प्रशासन ने इस दृष्टिकोण को जनता के सामने रखा, तो लोगों का जुड़ाव भावनात्मक हो गया। यह अभियान अब केवल सरकारी आदेश नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न बन गया है।

नवाचार: जब प्रतिस्पर्धा बनी प्रेरणा :- एक नवसृजित और ग्रामीण बाहुल्य जिले के रूप में डीग के सामने कई चुनौतियां थीं-तकनीकी साक्षरता की कमी, पुराने रिकॉर्ड्स की अनुपलब्धता और प्रवासन लेकिन हमने महसूस किया कि पारंपरिक ढर्रे से हटकर कुछ नया करना होगा। हमने दंड के बजाय प्रोत्साहन का मॉडल अपनाया। जब हमने प्रतिदिन उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को बेस्ट बीएलओ के रूप में सम्मानित करना शुरू किया, तो मैदानी अमले में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जाग उठी। परिणाम चौंकाने वाले थे- 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों पर भी कार्मिकों ने समय से पूर्व 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया। यह सिद्ध करता है कि यदि कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया जाए और उन्हें स्वामित्व का अहसास कराया जाए तो कठिनतम लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

कन्वर्जेंस- सिलोस को तोड़ना प्रशासनिक सफलता का मूल मंत्र समन्वय है। निर्वाचन कार्य को अक्सर केवल चुनाव शाखा की जिम्मेदारी मान लिया जाता है, लेकिन हमने इसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया। महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीएलओ के साथ शैडो वर्कर के रूप में जोड़ना एक निर्णायक कदम साबित हुआ। ग्रामीण परिवेश में जहाँ कई बार पर्दा प्रथा या अन्य सामाजिक कारणों से महिलाओं तक सीधी पहुँच मुश्किल होती है, वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर के भीतर तक पहुंचकर डेटा संकलन को सुगम बनाया। साथ ही, स्कूलों में छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला और रंगोली के माध्यम से अपने अभिभावकों को जागरूक करना-यह दर्शाता है कि जागरूकता अब कक्षाओं से निकलकर चौपालों तक पहुँच चुकी है।

शून्य त्रुटि की प्रतिबद्धता :- एसआईआर-2026 का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जो त्रुटिहीन हो। दोहरे पंजीकरण और मृत मतदाताओं के नाम हटाना एक बड़ी चुनौती रही है। हमने तकनीक का सहारा लेते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि डिजिटल प्रणाली अब दोहरी प्रविष्टि को स्वीकार नहीं करेगी। इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं और लोग स्वयं आगे आकर मतदाता सूची में सुधार करवा रहे हैं।

निष्कर्ष :- विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। यह एक पारदर्शी, समावेशी और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया है। डीग जिले में 68ङ्स से अधिक कार्य पूर्ण कर लेना और एक ही दिन में 50,000 से अधिक प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन करना, हमारी प्रशासनिक मशीनरी की बदलती कार्यसंस्कृति का प्रमाण है। यह अभियान सिद्ध करता है कि जब प्रशासन की इच्छाशक्ति और जनता का विश्वास एक साथ मिल जाते हैं, तो लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती हैं।

–उत्सव कौशल
(आईएएस),
डीग जिला कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के कारण और समाधान

प्रो. अशोक कुमार

प्रतियोगी परीक्षाएँ योग्यता-आधारित सामाजिक गतिशीलता की आधारशिला हैं। हालाँकि, प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं की बढ़ती संख्या ने इस पूरी प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक गहरा संकट उत्पन्न कर दिया है, जो लाखों युवा उम्मीदवारों के भविष्य और सार्वजनिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। यह संकट राष्ट्रीय महत्व का हो गया है।

हालिया प्रमुख घटनाएँ और प्रभावित छात्रों का डेटा हाल के वर्षों में लीक की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो इस संकट के विशाल पैमाने को दर्शाती है। 2024 में, कई महत्वपूर्ण भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फरवरी 2024 में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से लगभग 48 लाख युवा उम्मीदवार प्रभावित हुए। राज्य सरकार को यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी और इस घोटाले में शामिल 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी वर्ष, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (ळझ्झएण) द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) प्रारंभिक परीक्षा भी लीक का शिकार हुई, जिसके बाद इसे रद्द किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं ने व्यापक चिंता उत्पन्न की। NEET UG 2024 की परीक्षा, जिसमें 23 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे, पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स विवादों के कारण विवादों में घिर गई। जब परिणाम घोषित हुए, तो 67 छात्रों ने एक साथ शीर्ष रैंक हासिल की, जिससे अनियमितताओं का संदेह पैदा हुआ, और मामले की जाँच सीबीआई को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त, जून 2024 के केवल 10 दिनों के भीतर, NEET UG और UGC NET जैसी प्रमुख परीक्षाओं सहित चार बड़ी परीक्षाओं को स्थगित या रद्द करना पड़ा, जिससे प्रभावित छात्रों की कुल संख्या 38 लाख से अधिक हो गई। यूजीसी-नेट परीक्षा को उसके आयोजन के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि पेपर डार्क वेब पर लीक हो गया था। यह निरंतर और बड़े पैमाने पर लीक की घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि समस्या अब केवल स्थानीय प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय एजेंसियों की परिचालन क्षमता पर राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े करती है। परीक्षा लीकेज के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पेपर लीक के प्रभाव केवल परीक्षा रद्द होने तक सीमित नहीं हैं।

बार-बार परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों के मनोबल पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनमें लंबे समय तक तनाव और चिंता की स्थिति बनती है। इसके अतिरिक्त, तैयारी, कोचिंग और यात्रा में लगने वाली आर्थिक लागत भी बर्बाद हो जाती है। यह योग्यता-आधारित प्रणाली पर सीधा हमला है; लीक हुए पेपर कथित तौर पर 50,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक की रकम में बेचे जा रहे थे। यदि अयोग्य व्यक्ति डमी उम्मीदवारों या लीक हुए पेपर के माध्यम से प्रशासक बनते हैं, तो यह देश के प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। . पेपर लीक के मूल कारण: संस्थागत विफलता और संगठित अपराध पेपर लीक एक जटिल घटना है जो संस्थागत कमजोरियों और संगठित आपराधिक नेटवर्क की बढ़ती ताकत का परिणाम है। संस्थागत और प्रक्रियात्मक कमजोरियाँ परीक्षा प्रणाली की प्रक्रिया श्रृंखला में कई कमजोरियाँ हैं:

सुरक्षा चूक: प्रश्नपत्रों की छपाई और वितरण की पारंपरिक विधि में अक्सर मैनुअल हस्तक्षेप के कई बिंदु शामिल होते हैं, जिन्हें टचपॉइंट्स कहा जाता है। इन बिंदुओं पर सुरक्षा भंग हो सकती है।

लॉजिस्टिक्स में असुरक्षित टचपॉइंट: परिवहन और वेयरहाउसिंग का चरण अक्सर सबसे कमजोर कड़ी साबित होता है। लॉजिस्टिक्स जैसी कोर प्रक्रियाओं को निजी सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्स करना एक प्रमुख जोखिम उत्पन्न करता है, क्योंकि ये कंपनियाँ संगठित अपराध के लिए एक आसान प्रवेश द्वार (Entry Point) प्रदान करती हैं।

आंतरिक मिलीभगत: परीक्षा केंद्र स्वयं भी असुरक्षा के बिंदु बन सकते हैं, जहाँ केंद्र के कर्मचारियों की मिलीभगत से रिमोट एक्सेस टूल जैसे माध्यमों से नकल कराई जाती है।

संगठित आपराधिक सिंडिकेट्स की कार्यप्रणाली पेपर लीक अब अत्यधिक संगठित, अंतर-राज्यीय सिंडिकेट्स द्वारा संचालित होते हैं।

उच्च वित्तीय प्रेरणा: सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण के कारण, पेपर लीक संगठित अपराध के लिए एक उच्च लाभदायक व्यवसाय बन गया है। सिंडिकेट्स कमजोर कड़ी को निशाना बनाते हैं और लाखों रुपये कमाते हैं, जिससे यह एक अरबों रुपये का काला बाजार बन जाता है।

डमी उम्मीदवारों का इस्तेमाल: इन सिंडिकेट्स की कार्यप्रणाली में डमी उम्मीदवार (Proxy Candidates) का उपयोग करना एक प्रमुख तरीका है, जो शैक्षिणक रूप से योग्य होते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मूल उम्मीदवार की जगह परीक्षा में बैठते हैं।

प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग: ये गिरोह नकल के लिए परिष्कृत तकनीकें अपनाते हैं और पूरे परीक्षा चक्र (दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़) को निशाना बनाते हैं। कानूनी और दंडनीय ढाँचा: निवारण के प्रयास पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने दंडात्मक और निवारक कानूनों को सख्त किया है। लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में यह अधिनियम लागू किया, जो ळझ्एण, एएण, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और NTA द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को कवर करता है।

अपराध और दंड: सामान्य व्यक्तियों के लिए, न्यूनतम 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना है। संगठित अपराध पर कठोरता: संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के लिए 5 से 10 साल तक की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

सेवा प्रदाताओं के लिए दंड: यदि कोई सेवा प्रदाता (प्रिंटिंग प्रेस या लॉजिस्टिक्स) दोषी पाया जाता है, तो उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और उसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। राज्य-स्तरीय कानूनों की कठोरता उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 पेश किया है, जिसमें पेपर लीक करने पर आजीवन कारावास (उम्रकैद) तक की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान में भी पेपर लीक के लिए उम्रकैद और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है 3.3 दंडात्मक प्रावधानों का कार्यान्वयन कठोर कानून बनाना केवल आधा समाधान है। यदि जांच और अभियोजन की प्रक्रिया धीमी रहती है (जैसा कि राजस्थान के सख्त कानून में देखा गया है, जहाँ 2022 के कानून के तहत अभी तक किसी को प्रभावी सजा नहीं मिली है), तो कानून केवल कागज़ पर ही मजबूत रहता है। इसलिए, विधायी-कार्यात्मक अंतराल को समाप्त करने के लिए, पेपर लीक के मामलों की तेजी से सुनवाई और निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और जांच/फैसले के लिए 6 महीने की समय सीमा तय करना आवश्यक है।

दीर्घकालिक समाधान: संस्थागत अखंडता का रोडमैप पेपर लीक की समस्या का दीर्घकालिक समाधान केवल दंडात्मक कार्रवाई में नहीं, बल्कि संस्थागत अखंडता, प्रशासनिक पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार के रणनीतिक एकीकरण में निहित है।

प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक सुधार

NTA का पुनर्गठन और ऑडिट: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जैसी प्रमुख परीक्षा एजेंसियों में सुधार आवश्यक है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि NTA के संचालन में सुधार के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें लागू की जाएंगी, जिनमें परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार और तकनीकी अपग्रेडेशन शामिल हैं।

सुरक्षा प्रोटोकॉल का मानकीकरण: प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल हैंडलिंग को न्यूनतम करना चाहिए। लॉजिस्टिक्स जैसे चरणों को या तो अत्यधिक सुरक्षित सरकारी इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए या निजी सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता कम की जानी चाहिए। सभी कर्मचारियों की गहन पृष्ठभूमि जाँच अनिवार्य होनी चाहिए। अत्याधुनिक तकनीकी सुरक्षा उपायों का एकीकरण प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग परीक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है:-

सुरक्षित डिजिटल डिलीवरी: उन्नत एन्क्रिप्शन (Encryption) और डिजिटल वॉटरमार्किंग का उपयोग किया जाना चाहिए। जस्ट-इन-टाइम डिजिटल डिलीवरी' मॉडल अपनाया जा सकता है, जिसके तहत एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले सुरक्षित सर्वर के माध्यम से केंद्रों को भेजे जाते हैं। यह मुद्रण, भंडारण और परिवहन के दौरान लीक होने के जोखिम को समाप्त कर देता है।

बायोमेट्रिक सत्यापन और AI निगरानी: डमी उम्मीदवारों की समस्या को समाप्त करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट) और आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षाओं में एआई-आधारित रिमोट प्रोक्टरिंग और परीक्षा केंद्रों पर उन्नत सीसीटीवी का उपयोग करके संदिग्ध गतिविधियों की स्वचालित रूप से निगरानी की जा सकती है।

ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग: प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन (Blockchain) तकनीक का उपयोग एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। यह एक अपरिवर्तनीय (Immutable) लेजर प्रदान करता है, जिस पर प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर वितरण तक के प्रत्येक चरण को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

मूल्यांकन प्रणाली में संरचनात्मक सुधार दीर्घकालिक रूप से, शैक्षिक मूल्यांकन में संरचनात्मक सुधार किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में पारंपरिक रटने की प्रक्रिया से दूर हटकर योग्यता-आधारित मूल्यांकन (Competence-based assessment) और महत्वपूर्ण सोच (Critical Thinking) पर जोर दिया गया है। यदि परीक्षा का स्वरूप उच्च श्रेणी के कौशल और वैचारिक स्पष्टता की मांग करता है, तो पेपर लीक की वित्तीय प्रेरणा स्वत: ही कम हो जाएगी।

निष्कर्ष और नीतिगत सिफारिशें

पेपर लीक संस्थानो की योग्यता (meritocracy) पर एक सीधा हमला है। हालांकि कठोर दंडात्मक कानून (जैसे पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024) लागू किए गए हैं, लेकिन ये कानून तभी प्रभावी होंगे जब उन्हें अभेद्य तकनीकी सुरक्षा उपायों (AI, एन्क्रिप्शन) और मजबूत, ऑडिटेड प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत किया जाए। सरकार को सिस्टम पर निरंतर दबाव बनाना चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि केवल काबिल छात्र ही आगे बढ़ें। न्यायिक और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करके, सिंडिकेट्स के वित्तीय नेटवर्क (मनी ट्रेल) की गहराई से जांच करके और त्वरित न्याय सुनिश्चित करके ही इस संकट को समाप्त किया जा सकता है। परीक्षा संचालन में पूर्ण पारदर्शिता और निरंतर संचार बनाए रखना भी छात्रों के विश्वास को बहाल करने के लिए आवश्यक है।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

'आरपीएससी द्वारा शुरू की गई आवेदन विदड्रा सुविधा प्रभावी सिद्ध हो रही है'

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा शुरू की गई आवेदन विदड्रा सुविधा (आवेदन वापस लेने का अवसर) अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। आयोग के इस दूरदर्शी निर्णय ने न केवल राजकोषीय व्यय में उल्लेखनीय कमी की है, बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं की गति और पारदर्शिता को भी सुदृढ़ किया है। यह पहल उन अभ्यर्थियों को अवसर देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई, जिन्होंने वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद आवेदन कर दिया था। विदड्रा विकल्प उपलब्ध होने से अब केवल गंभीर और योग्य अभ्यर्थी ही प्रतिस्पर्धा में बने रहते हैं, जिससे परीक्षा आयोजन पर होने वाले अनावश्यक खर्च में भारी कमी आई है। प्रति अभ्यर्थी परीक्षा व्यय का न्यूनतम औसत जोड़े तो आवेदन वापसी के कारण हुई बचत करोड़ों रुपये तक पहुँच रही है।

आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि अनावश्यक आवेदनों के बोझ से मुक्ति मिलने से आयोग अब योग्य अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी और अंतिम चयन प्रक्रिया को अधिक तेज़ी और कुशलता से पूरा कर पा रहा है। उन्होंने इसे पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती तंत्र की दिशा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि अन्य भर्ती संस्थाएं भी इस नवाचार को अपना रही हैं। अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि वांछित योग्यता न होने के बावजूद आवेदन वापस नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कॉलेज शिक्षा) भर्ती-2024 में योग्यता नहीं होने के बावजूद चेतावनी के बाद भी आवेदन वापस नहीं लेने वाले 14 अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दर्ज करवाया गया है।

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यह नवाचार केवल वित्तीय बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है। लाखों की संख्या में अवांछित आवेदनों को प्रारंभिक चरण में ही अलग कर देने से प्रश्नपत्र मुद्रण, परीक्षा केंद्र प्रबंधन, सत्र निर्धारण और अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले भारी सार्वजनिक व्यय में उल्लेखनीय कमी हुई है।

न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ही आवेदन करने की अपील :-चूंकि आवेदन प्रक्रिया निशुल्क है, कई अभ्यर्थी अपनी योग्यता की जांच किए बिना ही आवेदन कर देते हैं, जिससे समय, धन और श्रम सभी का अपव्यय होता है। आयोग ने अपील की है कि अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और केवल वही उम्मीदवार आवेदन करें जो न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता रखते हों तथा परीक्षा में शामिल होने की वास्तविक इच्छा रखते हो। इससे परीक्षाओं का आयोजन सुचारू, समयबद्ध और निर्बाध रूप से हो सकेगा।

सार-समाचार

संविधान दिवस पर कार्यक्रम हुआ

पोकरण, (साबीर)। भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को दलित अधिकार अभियान समिति की ओर से स्थानीय अम्बेडकर सर्किल पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 76वें संविधान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष सुरेश नागौरा, शिक्षाविद रेंवताराम बारुपाल, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष नारायण रंगा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी अमृतलाल खत्री बन्धू सहित अनेक विशिष्टजन मौजूद रहे। अतिथियों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा भारतीय संविधान की गरिमा और महत्व पर अपने विचार प्रकट किए। वक्ताओं ने कहा कि भारत का संविधान विश्व में सबसे मजबूत और व्यापक संविधान माना जाता है, जिसने देश के हर नागरिक को समानता, न्याय, स्वतंत्रता और शिक्षा सहित अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं को मिले संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान ने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति तथा राजनीति में स्वतंत्र भागीदारी जैसे अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं आज हर क्षेत्र में अग्रसर हैं। कार्यक्रम में समिति उपाध्यक्ष चेतनराम भाटी, भगाराम देवपाल, मेहराजराम जुईया, हरिकिशन बारुपाल, भंवरलाल लीलावत, बाबूलाल पालीवाल, भील समाज अध्यक्ष नथूराम भील, बुधाराम भील, संजय लीलावत, विराट खान, श्रवण कुमार, रुघेश कुमार सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। समिति सचिव गणपतराम गर्ग ने उपस्थित जनों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। अंत में समिति अध्यक्ष सुरेश नागौरा ने सभी अतिथियों व नागरिकों का आभार व्यक्त किया।

वीर वीरमदेव कॉलेज में व्याख्यान

जालोर, (कासं)। वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में तथा नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के सहयोग से नशा मुक्ति जागरूकता विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एहसान अहमद, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अभियोजक, ने अपने उद्बोधन में संविधान के मूल्यों और नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सहायक आचार्य जगदीश सिंह राजपुरोहित ने भी संविधान के निर्माण प्रक्रिया, उसकी महत्ता तथा भारतीय लोकतंत्र में इसके योगदान पर प्रभावी व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करते हुए संविधान को जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य मनीष अखावत, डॉ. मनीष शेखावत, डॉ. शिवकुमार शर्मा सहित महाविद्यालय के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नशे के प्रति जागरूकता फैलाना, संविधान के आदर्शों से अवगत कराना तथा उन्हें जिम्मेदार, जागरूक और संवेदनशील नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करना था।

सफाई कर्मियों का झाड़ू डाउन धरना

फलोदी, (निसं)। फलोदी नगर परिषद के सफाई कर्मियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय समक्ष बुधवार दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन सफाई कर्मियों द्वारा अपनी मांग रखते हुवे बताया गया कि मृत आश्रित कर्मचारियों को काम तुरंत काम दिया जाये, कार्ड की पात्रता में शामिल किया जाये,पेंशन प्रकरण को जल्दी पूरा कर लाभ पहुंचाया जाये,दिवाली का बोनस और डी ए का बकाया भुगतान दिया जाये। साथ ही सफाई कर्मचारियों हेतु कॉलोनी काटने, जिससे की सफाई कर्मी आवास हीन न रहे जैसी समस्त मांगो को रखा गया था। लेकिन आज तक इनमें से कई मांगो को पूरा नहीं किया गया है । इसलिए अब हमें मजबूरन आंदोलन करने की राह पर आना पडा है। ज्ञापन में बताया गया कि सफाई कर्मियों द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के नाम 7 अक्टूबर 2025 को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उस ज्ञापन को जिम्मेदारों द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया जिसके चलते आखिरकार सफाई कर्मियों ने आंदोलन की राह पकडी है। ज्ञापन में बताया गया कि समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो समस्त सफाई कर्मी उग्र आंदोलन करेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

डूडसी ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल हुई

जालोर, (कासं)। जिला कलैक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने मंगलवार को डूडसी ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल कर उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए उनका मौके पर ही निस्तारण किया। रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलैक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे के समक्ष ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने, विद्युत व पानी की समस्या का समाधान करने सहित विभिन्न परिवाद प्रस्तुत किए जिनको जिला कलक्टर ने गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उनका मौके पर ही निस्तारण करवाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। रात्रि चौपाल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिस्कॉम व पंचायतीराज सहित विभागीय अधिकारियों ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व बड़ी संख्या ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

पिकअप ने ली खान मालिक की जान

जोधपुर, (कासं) । कमिश्ररेट में हुए सडक़ हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। इसमें एक खान मालिक बताया जाता है। पुलिस ने शवों को कार्रवाई के बाद परिजन के सुपुर्द किया। राजीव गांधी नगर पुलिस के अनुसार सूरसागर स्थित नई रकासनी एसबीआई बैंक रोड पर रहने वाला 52 साल का प्रहलाद सिंह पुत्र पन्नालाल अपनी खान से बाइक पर सवार होकर घर की तरफ से लौट रहा था। तब केरू रोड पर किसी पिकअप के चालक ने चपेट में ले लिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। इस बारे में उसके भतीजे महिपाल सिंह पुत्र पृथ्वीराज राजपुरोहित ने राजीव गांधी नगर थाने में पिकअप चालक के खिलाफ रिपोर्ट दी है। दूसरी तरफ बोरानाडा पुलिस ने बताया कि साडियानाडा की ढाणियां सैनाई लूणी निवासी धनसिंह पुत्र दलपत सिंह ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसके चाचा 62 वर्षीय चंदनसिंह पुत्र रामसिंह अपनी बाइक लेकर 17 नवंबर को भांडूकलां हाइवे रोड से निकल रहे थे। तब किसी वाहन चालक ने चपेट में ले लिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल उसके चाचा को एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मगर अब उनकी मौत हो गई। बोरानाडा पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजन को सौंपा।

मूलराजसिंह देवडा के निधन से शोक

रेवदर, (निसं)। रेवदर के निकट भटाना ठिकाना ठाकुर मूलराजसिंह देवडा के निधन पर कस्बे के सभी प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखी। बैकुट यात्रा में करीब बारह गांवों के हजारों लोग शामिल हुए। ठाकुर का निधन होने का संदेश मिलने पर कस्बे के आस पास गांवों के लोगों ने शोक मनाया ठाकुर की अंतिम यात्रा देखने के लिय लोग लाइन लगाकर हाथों में फूल लेकर खडे रहे। यात्रा में ठाकुर के परिवार वालों पैसे बरचाएं। ठाकुर साहब का स्वभाव निर्मल होने के कारण बैकुंठ यात्रा में हजारों लोगों की भीड रही। यात्रा में शिवगंज प्रधान, रेवदर विधायक मोती राम कोली, पूर्व विधायक जगसी राम कोली सहित कई नेता लोग मौजूद रहे।

बाबा साहेब को याद किया

रेवदर, (निसं)। राजकीय महाविद्यालय रेवदर में संविधान दिवस के मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर फूल अर्पित कर उनको याद दिया गया। इस दौरान प्राचार्य मुकेश कुमार मीणा में भारतीय संविधान के बारे में संक्षिप्त उद्बोधन दिया गया। इस आयोजित कार्य म में समस्त संकाय सदस्य कुलदीप सिंह , भंवर लाल, हंसराज, राजेश कुमार, छात्र लक्ष्मण वाघेला, हर्षवर्धन सिंह देवडा, एवं समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित थे।

जैसलमेर-दिल्ली नई ट्रेन 29 को

जैसलमेर, (नि.सं.)। केन्द्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत द्वारा 29 नवम्बर शनिवार को जैसलमेर से दिल्ली (शकूरबस्ती) नई ट्रेन का सुबह साढ़े दस बजे हरी झंडी दिखाकर जैसलमेर रेलवे स्टेशन से शुभारम्भ करें। उतर पश्चिम रेलवे जन सम्पर्क अधिकारी ने जानकारी दी। लम्बी दूरी की ट्रेनों के लिए तरस रहे जैसलमेर के लिए बड़ी खुशखबरी है। जैसलमेर से शकूर वस्ती (दिल्ली) के बीच यह ट्रेन रोजाना आवाजाही करेगी। इससे स्थानीय वाशिंदों व सैन्य बलों के लोगों के साथ पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

गंगानाथ महाराज का 9 वां चातुमार्स बैरठ में होगा

जालोर, (कासं)। सिरे मंदिर धाम के पीठाधीश्वर पीर गंगानाथ महाराज का 9 वां चातुमार्स बैरठ में सम्पन्न होगा।

भैरूनाथ अखाड़े के व्यवस्थापक पारसमल परमार ने बताया कि बुधवार को भैरूनाथ अखाडे में बैरठ ग्राम के समस्त ग्रामवासियों सहित उपस्थित भक्तजनों ने पीर गंगानाथ महाराज का अगला चातुर्मास गाँव बैरठ में करने का आग्रह किया। जिस पर पीर गंगानाथ महाराज ने भक्तों के आग्रह को स्वीकार किया। चातुर्मास की घोषणा करते ही बैठक में उपस्थित सभी भक्तों द्वारा नाथजी महाराज के जयकारो से सदन गुंजायमान हो उठा। इसके बाद भक्तों ने शुभ मुहूर्त में पीर गंगा नाथ महाराज को माला पहनाकर आशीर्वाद लिया। पीर गंगानाथ महाराज का बैरठ गांव में 9 वॉ चातुर्मास होगा। पीर गंगानाथ महाराज ने सन् 2014 विकम संवत 2071 मे प्रथम चातुर्मास भी बैरठ ग्राम में किया था। इसी ग्राम मे पीर गंगानाथ महाराज का यह दूसरा चातुर्मास होगा। इससे पूर्व भी बैरठ ग्रामवासियों ने पीर शांतिनाथजी महाराज का भी दो बार चातुर्मास सम्पन्न करवाया है । वहीं बैरठ में केशरनाथ महाराज भी दो बार चातुर्मास कर चुके है।

पीर गंगानाथ महाराज के आगामी चातुर्मास बैरठ गांव का प्रस्ताव स्वीकार करने पर ग्रामवासियों ने स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। फोटो-राष्ट्रदूत

बैरठ ग्राम के निवासी रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक गोपालसिंह ने बताया कि बैरठ ग्राम के समस्त ग्रामवासी नाथजी महाराज के भक्त है एवं पीर शांतिनाथजी महाराज, पीर गंगानाथ महाराज एवं समस्त नाथजी महाराज के प्रति प्रगाढ़ आस्था है। सभी भक्तों ने भैरूनाथ महादेव के समक्ष पूजा अर्चना कर बह्मलीन शांतिनाथजी महाराज की तस्वीर को माला पहनाकर केशरनाथजी की धूणी के दर्शन किये। समिति व्यवस्थापक पारसमल परमार ने समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद एवं साधुवाद ज्ञापित किया और समस्त भक्तगणों ने जय नाथजी री का उद्घोष किया।

संविधान की पालना करना हम सब का नैतिक कर्तव्य : अहसान अहमद

जालोर, (कासं)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश हारून के निर्देशन में बुधवार को संविधान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान राजकीय वीर वीरमदेव महाविद्यालय, राजकीय महिला महाविद्यालय एवं आशापूर्णा विधि महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

राजकीय गर्ल्स कॉलेज में युवा संसद का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अहसान अहमद ने भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत का संविधान सभी देशों से अच्छा संविधान है। संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर ने इसे बनाते समय सभी वर्गों का ध्यान रखा है। भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। संविधान भारत के सरकारी अंगों की संरचना, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इस दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाया गया। इस दौरान सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण को लेकर न्याय आपके द्वारा अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और अपनी शिकायतें दर्ज करवाने का तरीका बताया। इस दौरान प्राचार्य मोहम्मद इरफान, पीपाराम आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने के आवेदन पत्र एवं सेवाओं से संबंधित अभियान की जानकारी देने के लिए पोस्टर का वितरण किया गया। इसी प्रकार राजकीय वीर वीरमदेव महाविद्यालय में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव अहसान अहमद ने संविधान में आमजन के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। उन्होंने कहा कि डॉ बीआर अंबेडकर को संविधान का जनक और मुख्य वास्तुकार माना जाता है। इस दौरान सचिव ने विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कार्यवाहक प्राचार्य डॉ मनीष अखावत, एनएसएस प्रभारी मनीषसिंह, शिवकुमार शर्मा व सहायक आचार्य जगदीशसिंह राजपुरोहित मौजूद रहे। इसी प्रकार आशापूर्णा विधि महाविद्यालय में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संविधान दिवस के बारे में विस्तार से बताया और संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाया। इस मौके पर न्यायिक सक्रियता विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें पक्ष में वजाराम व सुमन ने एवं विपक्ष में भावेश ने अपना बेहतरीन पक्ष रखा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के पोस्टर, पंपलेट एवं जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करवाने के आवेदन पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम को अधिवक्ता डॉ प्रभूसिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान देवीलाल माली, डॉ हितेष आशिया, प्रशांत रामावत आदि मौजूद रहे।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष का जालोर, आहोर, सायला में स्वागत

जालोर, (कासं)। कांग्रेस की जालोर जिला की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमिला मेघवाल जालोर पहुंचने पर बुधवार को राजीव गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं जिलाध्यक्ष का आहोर , सायला में भी स्वागत किया गया।

जयपुर से जालोर आगमन पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शॉल ओढाकर, माला पहनाकर और गुलदस्ते भेंट कर गर्मजोशी से अभिनंदन किया। वही जयपुर से आहोर पहुंचने पर कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी के नैतत्र में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया।

स्वागत समारोह में कांग्रेस नेता पुखराज पाराशर, पूर्व जिलाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल, महिला जिलाध्यक्ष संतोष कंवर, कांग्रेस नेता उमसिंह चांदराई सहित बडी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। सभी ने मेघवाल को बधाई देते हुए संगठन को मजबूत करने की शुभकामनाएं दीं।

जिलाध्यक्ष रमिला मेघवाल ने कहा कि किसान, महिला, युवा और हर वर्ग के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जालोर में कांग्रेस को नई ऊर्जा और मजबूती के साथ आगे बढाया जाएगा।

राजस्थान जन अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं ढ्रष्टष्ट सदस्य पुखराज पाराशर के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें शॉल ओढाकर, माला हाथ में देकर सम्मानित भी किया।

कांग्रेस नेता उमसिंह चांदराई ने कहा कि रमिला मेघवाल के नेतृत्व में जिले का संगठन और सशक्त होगा। उन्होंने उन्हें जमीन से जुडी और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली नेत्री बताया। चांदराई ने विश्वास जताया कि नई जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं को नई दिशा और ऊर्जा देंगी।

कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष संतोष कंवर ने कहा कि रमिला मेघवाल की नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी है और इससे संगठन में नई गति आएगी। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल, आहोर प्रत्याशी सरोज चौधरी, उपाध्यक्ष जुल्फिकार अली भूटो, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सुष्मिता गर्ग, प्रदेश सचिव कामिनी शर्मा, गीताश्री, पुर्व पार्षद बंसत सूथार, ममता जैन, पुर्व पार्षद अफरोजा सिलावट सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सायल नगर के कात्यायनी माताजी मंदिर परिसर में बुधवार दोपहर को मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत सायला ब्लॉक कांग्रेस एवं नगर कांग्रेस के सभी बीएलए की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का नेतृत्व प्रभारी परीक्षित व्यास ने किया।

कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण, नए मतदाताओं के पंजीयन, आपत्तियों के निस्तारण तथा बूथ लेवल की जिम्मेदारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। वक्ताओं ने बीएलए की भूमिका को चुनाव प्रक्रिया की रीढ बताते हुए संगठन के प्रति जिम्मेदारी और सजगता से कार्य करने का आहवान किया।

इस दौरान जालोर जिला कांग्रेस की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्रीमती रमिला मेघवाल का गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया और संगठन को मजबूती देने की दिशा में उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सवाई सिंह चंपावत ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त कर संगठनात्मक मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संदेश दिया।

इस दौरान सेवा दल जिलाध्यक्ष भेरूपाल सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सवाई सिंह चंपावत, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुखदेव त्रिवेदी, जिला महासचिव सुल्तान खान भाटी, नगर अध्यक्ष नागेश जैन, सुष्मिता गर्ग आदि मौजूद रहे।

कृषि वि.वि. में संविधान दिवस मनाया

जोधपुर, (कासं) । कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. डॉ वीएस जैतावत ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को पूर्णता देने के लिए कृषि क्षेत्र एवं कृषि वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। कुलगुरु प्रो जैतावत ने यह बात बुधवार को कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि हमें ऐसे अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार उपलब्ध करवाने हैं जो न केवल किसानों के जीवन को समृद्ध बनाएं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी सुदृढ़ करें। उन्होंने कहा कि आज हम संकल्प लेवें की राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाकर भारत को आत्मनिर्भर और समृद्धि की राह पर बढ़ाएंगे। उन्होंने संविधान की गरिमा को अपनाते हुए इसके आदर्शों को अपनाने की भी बात कही। कार्यक्रम में मौजूद निदेशक शिक्षा, डॉ एस के मूंड ने संविधान निर्माण की चर्चा करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े होने के नाते हम सबका पुनीत कर्तव्य है कि अन्नदाता के प्रति हमारे कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करें। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों की ओर से संविधान की उद्देशिका का वाचन भी किया गया। विश्वविद्यालय के सभी डीन, निदेशक, अधिकारी व कर्मचारीयों सहित विद्यार्थी मौजूद रहे।

रेवदर पंचायत समिति में साधारण सभा आयोजित

रेवदर. (निसं)। पंचायत समिति रेवदर के सभा भवन में प्रधान राधिका देवासी की अध्यक्षता में साधारण सभा बैठक का आयोजित किया गया।

बैठक में विधायक मोतीराम कोली का आतिथ्य रहा। बैठक मे विभिन्न विभागों के अधिकारी एव कर्मचारीगण मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विधायक ने बताया कि सुकडी सेलवाडा नहर के पास पट्टेधारी 16 परिवारों को भूमि अवाप्ती का मुआवजा नहीं मिलने के संबंध में जल संधाधन विभाग को अगवत कराया। प्रत्येक ग्राम पंचायत की गोचार भूमि में एक पशुशेड निर्माण करवाने के संबध में चर्चा की। तहसीलदार मंजू देवासी द्वारा एस आई आर एवं राजस्व विभाग के संबधित जानकारी दी गई।

बैठक में विकास अधिकारी हेमाराम चौधरी ने नरेगा स्वामित्व, पेंशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दी। बैठक में जेजेएम में तोडी गई सडको को पुनः मरम्मत करवाने तथा पानी की नियमित आपूर्ति के बारे जलदाय विभाग को अवगत कराया गया।

बैठक में ग्राम पंचायत पोसीतरा के डामर सडक के पास लगे ट्रसफार्मर को अन्यत्र शिप्ट करने के बारे बताया। विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता ने स्मार्ट मीटर व सोलर सिस्टम लगाने के बारे में जानकारी दी।

पोसीतरा में सीएससी पर एएनएम लगाने एवं चिकित्सा संबधित विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में शिक्षा विभाग एवं बाल विकास विभाग के संबधित विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सेन्टर खोलने के बारे चर्चा की गई। बैठक में प्रधान द्वारा धन्यवाद उपरान्त बैठक का समापन किया गया। बैठक में उप प्रधान उर्मीला देवी वैष्णव, जिला परिषद सदस्य मगनलाल कोली, पंचायत समिति सदस्य सुरताराम, नरसाराम माली, प्रतापराम, शंकरलाल कोली, पंख देवी, प्रागाराम एवं प्रशासक अजबाराम, महेन्द्र कुमार, गुलाब कुंवर, पीराराम एवं अति. विकास अधिकारी भरत सिंह, हरिश प्रकाश सोनी, कनिष्ठ सहायह हरिश दवें, कानाराम आदि मौजूद रहे।

शोभायात्रा निकाली

पाली, (नि.सं.)। पाली शहर के धान मंडी पुरानी कचहरी स्थित माता रानी भटियाणी मंदिर की 19वीं वार्षिक उत्सव के तहत बुधवार को सुबह 9 बजे बैंड बाजा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। सैकड़ो महिला पुरुषों ने केसरिया ध्वज लेकर शोभायात्रा में शामिल हुए।,

शोभायात्रा में ग्रामीण क्षेत्र से आई गेर नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। शोभायात्रा में घोड़े पर सवार युवक एक गाड़ी में माताजी की सवारी जयकारे लगाते भक्तगण चल रहे थे। मंदिर पुजारी दिनेश राठौर ने बताया कि शोभायात्रा धान मंडी से शुरू होकर सोमनाथ मंदिर भेरू घाट पानी दरवाजा उदयपुरिया बाजार गुलजार चौक पुरानी सब्जी मंडी होते हुए वापस माता रानी मंदिर पहुंच समाप्त हुई। जहां माता जी की आरती हुई तीन दिवसीय कार्यक्रम में पाली शहर के अलावा अन्य जगह सभी भक्तगण पहुंचे।

जल शक्ति अभियान कैच द रेन के कार्यों की समीक्षा

जालोर, (कासं)। जल शक्ति अभियान-कैच द रेन 2025 की केंद्रीय नोडल अधिकारी एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक रंजिता रश्मि की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जल शक्ति अभियान-कैच द रेन 2025 के तहत जालोर जिले में पूर्ण किए गए जल संरक्षण कार्यो की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान केंद्रीय नोडल अधिकारी रंजिता रश्मि ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से जिले में जल संचय-जन भागीदारी अभियान, नेशनल वॉटर मिशन, अमृत सरोवर 2.0 सहित विभिन्न प्रगतिरत जल संरक्षण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने जिले में संचालित हर घर जल-जल जीवन मिशन के अंतर्गत नर्मदा नहर परियोजना के एफआर, डीआर, ईआर एवं सीलु-जैसला-भाटकी प्रोजेक्ट की प्रगति देखी।

उन्होंने प्रधानमंत्री .षि सिंचाई योजना के अंतर्गत जिला परिषद की तरफ से करवाए गए विभिन्न कार्यों- टांका निर्माण, फॉर्म पौंड निर्माण, रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम कार्यों तथा जल संसाधन विभाग द्वारा सम्पादित करवाये जा रहे भैंसवाड़ा डाइवर्जन कार्य पर जानकारी लेने के साथ ही जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर जिला कलैक्टर डॉ प्रदीप के गावंडे, केन्द्रीय भू-जल ब्यूरो के वैज्ञानिक घनश्याम तिवारी, उप वन संरक्षक जयदेव सिंह चारण, जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिदंबरा परमार, पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा, अधिशासी अभियंता लक्ष्मणसिंह सांदू, जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता विजेश कुमार बालेसा, सहायक वन संरक्षक भंवरसिंह सोढ़ा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पाली में उत्कृष्ट कार्य पर बीएलओ का सम्मान

पाली, (नि.सं.)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत परिगणना प्रपत्रों के शत प्रतिशत डिजिटलाइजेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पाली जिले के बीएलओ को मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर एलएन मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी मंत्री ने बीएलओ नंदेश कुमार (बाली), रूपसिंह गोयल (पाली), इकबाल मोहम्मद (सुमेरपुर), अंकुश सुधार सोजत, जवाहरलाल सोजत, नवीन राजपुरोहित (सोजत), प्रकाशचन्द्र मेवाड़ा (सोजत), ओमप्रकाश विश्नोई (पाली), विक्रम सिंह (पाली), नरसिंहराम (पाली), सुरेन्द्र सिंह (मारवाड़ जंक्शन), सरेन्द्र कुमार लौहार, बाबूलाल मेघवाल (मारवाड़ जंक्शन), हजारीसिंह (मारवाड़ जंक्शन), गिरधारी सिंह (मारवाड़ जंक्शन), रगाराम भटनागर (मारवाड़ जंक्शन), प्रेमसिंह पेमावत (बाली), लालचन्द मीणा (बाली), गोविन्दसिंह सिन्दल (सुमेरपुर), महेश कुमार वैष्णव (सुमेरपुर) को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य कर पुनरीक्षण प्रक्रिया को गति प्रदान की गई है। उन्होंने बेहतर कार्य के लिए सभी बीएलओ का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. बजरंग सिंह, नोडल अधिकारी (स्वीप) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मुकेश चौधरी, जिला स्वीप समन्वयक गजेन्द्र सिंह नारलाई, तथा बीएलओ सहायक सत्यनारायण शर्मा उपस्थित रहे।

शंभू सिंह खेतासर परिवार को 18 साल बाद मिला न्याय

पाली, (निसं)। जिला न्यायालय पाली के जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने वर्ष 2006 से लंबित आरएफसी की नीलामी विवाद से जुड़े तीन प्रकरणों का एक साथ निस्तारण करते हुए एक अहम फैसला सुनाया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी नीलामी में मात्र सर्वाधिक बोली लगाने से बोलीदाता को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता और नीलामी को निरस्त करना तथा पुनः नीलामी करना आरएफसी का अधिकार है।

शंभूसिंह खेतासर परिवार के अधिवक्ता वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अरोड़ा ने बताया कि 2 नवम्बर 2006 को आरएफसी ने प्लॉट संख्या 2, सुभाष नगर 'बी', पाली की नीलामी आयोजित की थी, जिसमें सर्वाधिक बोली 58,21,000 की रवि मोहन भूतड़ा के नाम रही। बाद में आरएफसी ने इस नीलामी को रद्द कर दिया और 6 अगस्त 2007 को पुनः नीलामी घोषित की। रवि मोहन भूतड़ा ने पुनः नीलामी को रुकवाने हेतु दावा एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु विचारण न्यायालय तथा तत्पश्चात जिला न्यायालय दोनों ने उनका स्थगन आवेदन खारिज कर दिया। इस अवधि में पुनः हुई नीलामी में शंभू सिंह खेतासर के पुत्र राजेंद्र सिंह ने 76,31,000 की सर्वाधिक बोली लगाई और संपूर्ण राशि जमा भी करवा दी। उधर, रवि मोहन द्वारा जिला न्यायालय पाली के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में उच्च न्यायालय ने आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे राजेंद्र सिंह के पक्ष में लीज निष्पादित नहीं हो सकी। इस बीच रवि मोहन ने संविदा की विशिष्ट पालना का एक नया वाद भी जिला न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। उसके विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय ने रवि मोहन का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद का निर्णय रवि मोहन के पक्ष में कर दिया, जिसे आर एफ सी और राजेंद्र सिंह ने जरिए अपील जिला न्यायालय में चुनौती दी।

इस दौरान राजेंद्र सिंह का स्वर्गवास हो गया तो राजेंद्र सिंह के स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा कार्यवाही जारी रखी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा ने शंभू सिंह खेतासर परिवार की ओर से पैरवी करते हुए तर्क दिया कि सिर्फ सर्वोच्च बोली लगा देने से रवि मोहन भूतड़ा को कोई अधिकार अर्जित नहीं होते, आरएफसी को नीलामी रद्द करने एवं पुनः नीलामी करने का पूर्ण अधिकार है। पुनः नीलामी में राजेंद्र सिंह का अधिकार वैध एवं संरक्षित है। रवि मोहन को आरएफसी व राजेंद्र सिंह के मध्य हुई संविदा को चुनौती देने का कोई हक नहीं है।

जिला न्यायाधीश पाली राजेंद्र कुमार ने सभी तर्कों पर विचार करने के बाद आरएफसी व राजेंद्र सिंह द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए रवि मोहन भूतड़ा के दोनों दावों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रमुख रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि सर्वाधिक बोली मात्र से कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता। नीलामी निरस्त करना और पुनः नीलामी करना आरएफसी का अधिकार है, तथा पुनः नीलामी में खरीददार (राजेंद्र सिंह) के अधिकार को चुनौती देने का रवि मोहन भूतड़ा को कोई आधार नहीं है। इस निर्णय को नीलामी विवादों में एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।

कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)

Tel - (02973)222270 अस्पताल चौराहा, जोधपुर रोड जालोर (राज.) पिन नं. 343001 E-mail: mbjalore24@yahoo.in

क्रमांक: नपजा/भूमिशाखा/2025/ 5854 दिनांक: 26/11/2025

-:: आपत्ति आमंत्रण सूचना ::-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है । कि नगर परिषद् क्षैत्र जालोर के 69 ए के पट्टे के बदले पट्टा व खांचा भूमि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाकर पट्टे की मांग की गई है । इस संबंध में किसी व्यक्ति आदि को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो लिखित प्रार्थना - पत्र साक्ष्य आपत्ति सूचना पत्र के प्रकाशन होने के 07 दिवस व भीतर -भीतर नगर परिषद् कार्यालय को प्रस्तुत करे । निर्धारित समयावधि उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी एंव आवेदको के नाम पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जायेगी ।

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	आवेदक का नाम/पता	अडौस-पडौस चतुर्थदर्शी	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गगज)	प्रयोजन का प्रकार
1	104/2025-26	शाति देवी पत्नी मसरा राम / दुकान नं.-94 हेड पॉस्ट ऑफिस मेन रोड, जालोर।	उत्तर- दुकान संख्या -95 दक्षिण- रास्ता। पूर्व- हेड पॉस्ट ऑफिस रास्ता। पश्चिम- 10 फीट	61.11	वाणिज्य
2	105/2025-26	प्रकाश सोलंकी पुत्र पुनमाराम सोलंकी / दुकान सं.- 91 ए हेड पॉस्ट ऑफिस मेन रोड, जालोर	उत्तर- दुकान संख्या- 91 बी दक्षिण- दुकान संख्या - 90 पूर्व- हेड पॉस्ट ऑफिस रास्ता। पश्चिम- रास्ता।	61.11	वाणिज्य

आयुक्त, नगर परिषद् जालोर

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : राजस्थान में हाईवे से हटेंगे शराब के ठेके

'हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रहे सभी 1102 शराब के ठेकों को 2 महीने में हटाये जाए'

- **राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेकों को लेकर हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया**
- **राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने हाईवे को लिकर-फ्रेंडली कॉरिडोर बना डाला**
- **कोर्ट ने हाल ही में जयपुर के हरमाड़ा (15 मौतें) और फलोदी (15 मौतें) में हुए भीषण सड़क हादसों का हवाला देते हुए कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा साबित हो रहा है**

जोधपुर। राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेकों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रहे सभी 1102 शराब के ठेकों को 2 महीने के भीतर हटाने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते समय सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने म्युनिसिपल एरिया की आड़ में हाईवे को लिकर-फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाहे ये ठेके नगरपालिका या शहरी सीमा में ही क्यों न आते हों, अगर ये हाईवे पर है, तो इन्हें हटाना ही होगा। यह फैसला प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों और ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों को देखते हुए दिया गया है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि प्रदेश में कुल 7665 शराब की दुकानों में से 1102 दुकानें नेशनल और स्टेट हाईवे पर है। सरकार की दलील थी कि ये दुकानें आबादी/नगरपालिका क्षेत्र में आती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की छूट के दायरे में है। सरकार ने यह भी बताया कि इन 1102 दुकानों से राज्य को सालाना करीब 2221.78 करोड़ रुपए का भारी-भरकम राजस्व मिलता है।

हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मजाक बना दिया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों की जान की सुरक्षा सर्वोपरि है। 2200 करोड़ रुपए के राजस्व के लिए हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। प्रदेश में करीब 7765 शराब की दुकानें हैं। इनसे विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17 हजार 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित हुआ था। यह प्रदेश में किसी सरकारी विभाग में सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। कोर्ट ने बताया कि 2025 में अब तक ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में करीब 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सितंबर 2025 तक ऐसे 43,788 मामले सामने आ चुके हैं। कोर्ट ने हाल ही में जयपुर के हरमाड़ा (15 मौतें) और फलोदी (15 मौतें) में हुए भीषण सड़क हादसों का हवाला देते हुए कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा साबित हो रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में 2 टूक निर्देश दिए हैं

500 मीटर का दायरा :- नेशनल या स्टेट हाईवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी शराब की दुकान संचालित नहीं होगी। सरकार को ये 1102 दुकानें 2 महीने के भीतर शिफ्ट करनी होंगी। शराब का कोई भी होर्डिंग या विज्ञापन हाईवे से दिखाई नहीं देना चाहिए। अगली सुनवाई 26 जनवरी 2026 को होगी, जिसमें आबकारी आयुक्त को पालना रिपोर्ट पेश करनी होगी।

3.20 करोड़ का डोडा-चूरा जब्त, तीन तस्कर गिरफ्तार

आसींद पुलिस ने ट्रक से अवैध अफीम डोडा-चूरा जब्त कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया।

- **ट्रक से 21 क्विंटल 29.620 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा जब्त किया**
- **ट्रक में ऊपर कपास काकड़ा (कॉटन शीड्स) के कट्टे भरे थे, जिसकी आड़ में नीचे छिपाकर रखे गए अफीम डोडा-चूरा के कट्टे मिले**

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के आसींद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना आसींद ने नेशनल हाईवे 158 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 21 क्विंटल 29.620 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 20 लाख है। इस दौरान पुलिस ने तस्करी में शामिल तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा धर्मेन्द्र सिंह के आदेशानुसार यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सेक्टर सहाडा बुधराज खटीक के निर्देशन और पुलिस उप अधीक्षक वृत आसीन्द ओमप्रकाश सोलंकी के सुपरविजन में, थानाधिकारी आसींद हंसपाल सिंह उ.नि. के नेतृत्व में एक टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

कस्बा आसींद में नेशनल हाइवे-158 पर सवाईभोज पेट्रोल पम्प के पास थानाधिकारी हंसपाल सिंह मय जाप्ता द्वारा नाकाबंदी कर वाहनों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी। भीलवाड़ा की तरफ से आए एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया। चालक और उसके दो साथी भरे हुए माल के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। शंका होने पर ट्रक को सर्विस रोड पर लाकर नियमानुसार चैकिंग की गई। ट्रक में ऊपर कपास काकड़ा (कॉटन शीड्स) के कट्टे भरे थे, जिसकी आड़ में नीचे छिपाकर रखे गए अफीम डोडा-चूरा के 103 कट्टे मिले। मापतौल करने पर 21 क्विंटल 29.620 किलोग्राम डोडा चूरा पाया गया, जिसे तस्करी में प्रयुक्त ट्रक सहित जब्त कर लिया गया।

थाना प्रभारी हंसपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया गया है। पुलिस ने देवेंद्र पिता मोहनलाल दांडी, पारस पिता चीना राम के साथ बंशीर पिता हमजा खान को गिरफ्तार किया।

कोटा : तिलम संघ का जी.एम. तीस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी बारां की टीम ने तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

- **तिलम संघ के महाप्रबंधक ने परिवादी से न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र आवंटित करने के एवज में 1.45 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी**

कोटा, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) बारां की टीम ने बुधवार दोपहर कोटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए तिलम संघ के जी.एम. (महाप्रबंधक) रमेश चंद बैरागी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तिलम संघ के महाप्रबंधक न्यूनतम समर्थन मूल्य का खरीद केंद्र आवंटन करने की एवज में लाखों रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। पहली किस्त के 30 हजार रुपए लेते हुए उन्हें एसीबी की टीम ने पकड़ लिया।

एसीबी बारां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालूराम वर्मा ने बताया कि बारां जिले के पलायथा निवासी एक परिवादी ने शिकायत की थी कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र संचालित करना चाहते हैं और इसके लिए तिलम संघ में आवेदन किया था। खरीद केंद्र आवंटित करने के एवज में तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी ने उनसे 1.45 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। कालूराम वर्मा ने बताया कि मंगलवार को परिवाद का सत्यापन कराया गया जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद बुधवार को ट्रैप टीम गठित की गई। परिवादी ने पहली किस्त के रूप में 30 हजार रुपये महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी को रावतभाटा रोड़ स्थित तिलम संघ कार्यालय में दिए। इसी दौरान एसीबी की टीम ने दबिश देकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वत की राशि भी मौके से बरामद कर ली गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी रमेश चंद बैरागी के ठिकानों पर भी एसीबी की टीमें रवाना की गई हैं, जहां तलाशी और आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाएगी।

नाबालिग को बालश्रम से मुक्त करवाया

सीकर, (निसं)। जिला प्रशासन एवं जिला टास्क फोर्स की सख्ती से दादिया थाना पुलिस द्वारा एक होटल से 14.5 वर्षीय नाबालिग को बालश्रम से मुक्त करवाया गया। यह कार्रवाई दादिया थाना पुलिस, बाल कल्याण समिति एवं गायत्री सेवा संस्थान की संयुक्त पहल के तहत की गई। कार्रवाई के दौरान दादिया थाना से बाल कल्याण अधिकारी रोहिताश कुमार, तथा जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस एवं गायत्री सेवा संस्थान की ओर से फील्ड कोऑर्डिनेटर अभिषेक बगडियां तथा जितेंद्र नाथवतपुरा सक्रिय रूप से मौजूद रहे। रेस्क्यू किए गए बालक से प्रतिदिन 10-12 घंटे तक मजदूरी करवाई जा रही थी। रेस्क्यू के उपरांत बालक को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंकुर बहड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे कस्तूरबा सेवा संस्थान, भादवासी में अस्थाई आश्रय प्रदान किया गया।

77 ई-मित्र कियोस्क का निरीक्षण

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में कई जगहों पर ई मित्र संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जिला कार्यालय ने 77 ई-मित्र कियोस्क का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने पर कई कियोस्क बंद किए गए और संबंधित धारकों पर जुर्माने भी लगाए गए।

संयुक्त निदेशक नवीन माथुर ने बताया कि ओसियां की सुनीता को ई-मित्र धोखाधड़ी में दोषी पाते हुए कियोस्क को स्थायी रूप से बंद करने की अनुशंसा की गई है। चामू के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के भेर सिंह देवड़ा, महाजन का बास के प्रीति और सवाई किशन राठी, सेखाला बस स्टैंड के कुम्भा राम और जगदीश कुमार के कियोस्क बंद पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया।

सेखाला के गड़ा के केवल राम को कियोस्क की गलत जगह के कारण और बावड़ी के राजीव गांधी सेवा केन्द्र के छैल सिंह को सेवा अस्वीकृति पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा। श्याम मनोहर नगर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के दीपक सैन और जगदीश पर को-ब्राण्ड व आईडी कार्ड त्रुटियों के लिए 7 दिन कियोस्क बंद और 5000 रुपये जुर्माना लगाया गया। पाल बालाजी मंदिर के सामने शिवराम चौधरी को आईडी कार्ड, को-ब्राण्ड और अधिक वसूली की अनियमितताओं के लिए 15 दिन कियोस्क बंद और 5000 रुपये का जुर्माना किया गया। बिलाड़ा बस स्टैंड पर घनश्याम पटेल को आईडी कार्ड, सेवा अस्वीकृति, को-ब्राण्ड व अधिक वसूली के लिए 15 दिन कियोस्क बंद रखने का दंड मिला।

सेवानिवृत अधिकारी को झांसा देकर 9.41 लाख की ठगी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सेवानिवृत हुए सहायक अधिकारी को धन दुगुना करने के नाम पर शातिरों ने झांसे में लेकर 9.41 लाख की ठगी कर ली। सायबर ठगी का अहसास होने पर रिटायर्ड अधिकारी ने शिकायत दी तब 1.99 लाख होल्ड करवाए गए, मगर शेष रकम डूब गई। उन्होंने अब महामंदिर थाने में धोखाधड़ी में रिपोर्ट दी है।

जानकारी के अनुसार सी-107 पावटा स्थित धर्मनारायण का हत्था में रहने वाले नवीनचंद्र कौशिक की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई है। इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला सेशन न्यायालय) से सहायक अधिकारी के रूप में 30 अगस्त 25 को सेवानिवृत हुए थे। सरकारी नौकरी में रहते उनके परिलाभ जीपीएफ की राशि 11 लाख रूपए 16 अक्टूबर 25 को खाते में जमा हुई थी। उसी दिन मोलिक नाम के एक शख्स का कॉल आया कि वह गुजरात की कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत है और उसकी कंपनी में निवेश के लिए कहा। उसने कहा कि धन निवेश पर एक माह में धन दोगुना कर दिया जाएगा।

इस पर नवीनचंद्र ने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। मगर कुछ रोज बाद में उनके पास में प्रदीपसिंह नाम के शख्स का कॉल आया और कहा कि उसने मोलिक के स्थान पर मैनेजर का पद संभाला है और वह धन दुगुना करने की बात कहने लगा। उसकी बातों में आए सेवानिवृत नवीनचंद्र ने 16 अक्टूबर 25 को उसके बताए खाते में 75 हजार रूपए निवेश किए, फिर 17 अक्टूबर को 2.50 लाख जमा कराए गए। यह रूपए भदोई की आइडीएफसी शाखा में जमा कराए गए।

बाद में उसने अपने एकाउंटेंट रतनेश गुप्ता के नंबर भी दिए जिस पर अनिता शाह नाम की महिला के खाते में 3.66 लाख रूपए जमा कराए गए। पीड़ित नवीनचंद्र कौशिक ने बताया कि बाद 18 अक्टूबर को जब प्रदीप सिंह को कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया, फिर उसने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। इस पर रिटायर्ड नवीनचंद्र को ठगी का अहसास होने पर उन्होंने पुलिस लाइन पहुंच कर सायबर ठगी की शिकायत दी। इस पर पुलिस ने 1 लाख 99 हजार 818 रूपए होल्ड करवाए, मगर शेष रकम आज तक नहीं मिली। अब उनकी तरफ से महामंदिर थाने में रिपोर्ट दी गई है।

राजस्थान से सिम एक्टिवेट कराकर दूसरे देशों में भेजी, तीन गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (निसं)। पुलिस ने तीन सायबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग राजस्थान में सिम एक्टिवेट करवाकर साउथ-ईस्ट देशों के ठगों को बेच देते थे। ये आरोपी सायबर ठगी की बैंक में होल्ड पड़ी रकम निकलवाने के भी माहिर थे। फर्जी मोहरे और लेटर पेड बना कर बैंक से होल्ड रकम निकलवा लेते। ये ठगी के रुपयों से चांदी खरीद रहे थे। इनके पास पुलिस को 21 किलो की चांदी और 21 लाख कैश बरामद हुआ है। इस मामले में श्रीगंगानगर में एक मुकदमा एयरटेल कंपनी ने दर्ज कराया, जबकि दो मुकदमे पुलिस ने खुद दर्ज किए। एक मुकदमा घड़साना थाने में और एक मटीली राठान थाने में दर्ज हुआ था। बुधवार को एसपी अमृता दुहन ने तीन सायबर ठगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया।

एसपी अमृता दुहन ने बताया कि मामले में चंद्र कुमार, संदीप चौहान व दीपक के रूप में पहचान हुई है। तीनों बदमाश श्रीगंगानगर शहर के रहने वाले हैं। इनके पास से 90 चेक बुक, 13 बैंक पासबुक, 64 एटीएम कार्ड, 44 एक्टिव सिम कार्ड, लोगों के आधार, पैन व जन आधार कार्ड, 12 रबर स्टाम्प मोहरे, 23 बिल बुक, लैपटॉप, फर्जी कंपनियों के जीएसटी नंबर व डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। आरोपियों का बड़ा नेटवर्क है जो लोगों को झांसे में लेकर सायबर ठगी करते थे। इनसे पूछताछ कर नेक्सस की जानकारी जुटाई जा रही है।

एसपी ने बताया कि तीनों आरोपी बैंक अकाउंट को खरीदने और बेचने का काम भी करते थे, जिससे उन्हें बड़ा प्रॉफिट होता था। आरोपियों ने बताया है कि इनका सायबर ठगी करने वाला बड़ा नेटवर्क है। आरोपी गरीब लोगों को ढूंढ कर उनके एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, चेकबुक और एक्टिव सिम कार्ड ले लेते थे। जिसके बाद उनके किट बनाकर बड़े सायबर ठगों को प्रोवाइड कराते थे। फिर वह ठग बड़े स्तर पर इन गरीबों के बैंक एकाउंट्स में सायबर ठगी के पैसे का लेनदेन करते थे। आरोपी एक व्यक्ति की किट 50 हजार में बेचते थे। लोगों को दो-तीन हजार का प्रलोभन देकर उनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते थे और उनके नाम से सिम एक्टिव करवा ली जाती थी।

एसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने कुछ बड़े एकाउंट्स के साथ सायबर फ्रॉड भी किया था। जिनके बैंक अकाउंट्स बैंक ने होल्ड कर दिए थे। इन बैंक अकाउंट्स को होल्ड में से निकलवाने के लिए आरोपियों ने फर्जी मोहर, जीएसटी नंबर और कई प्राइवेट कंपनियों की लेटर पैड बनवा रखी थी। आरोपी फर्जी लेटर पैड बनाकर बैंक में जाते और होल्ड हुए अकाउंट को एक्टिवेट करवा लेते। इसके बाद वह बैंक द्वारा होल्ड किए गए पैसे आसानी से निकलवा लेते।

एसपी ने बताया कि पिछले कुछ समय से साउथ ईस्ट कंट्री (कम्बोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया) में भारत के सिम एक्टिवेट हो रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारे देश में सायबर फ्रॉड हो रहा है। एसपी ने बताया कि जब भी कोई कस्टमर किसी भी कंपनी की सिम लेने जाता है तो एजेंट वेरिफिकेशन के लिए बार-बार ओटीपी और फिंगरप्रिंट लगवाता है। इसके बाद एक बार ही में कई सिम एक्टिवेट हो जाती है। कस्टमर को सिर्फ एक ही सिम दी जाती थी और बाकी सिम में अर्जेंट खुद एक्टिवेट कर इन्हें आगे भेज देते थे। जिसके बाद सायबर ठग इन एक्टिवेट सिमों से देश भर में सायबर ठगी करते थे। बिहार पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

30 साल की महिला से दुष्कर्म

सीकर, (निसं)। सीकर जिले में 30 साल की महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने झुग्गी में घुसकर महिला पानी में नशीला पदार्थ पिलाया, फिर रेप किया। इतना ही नहीं इस दौरान आरोपी के साथी ने महिला का अश्लील वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि 24 नवंबर की दोपहर को तीन बजे आरोपी युवक नशे में धुत होकर उसकी झुग्गी में आया। उसने बच्चों और पिता के सामने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद मारपीट कर रेप किया। आरोपी के एक साथी ने महिला का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के वक्त वहां अन्य भी कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने आरोपी को नहीं रोका। इस दौरान आरोपी महिला की झुग्गी से 50 हजार रुपए भी लूटकर ले गया। महिला ने तीन नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।

दंपती की कार दुर्घटना में मौत

जोधपुर, (कासं)। निकटतर्वी मथानिया के उम्मेद नगर में रात एक बजे सड़क हादसे में दंपती की दर्दनाक मौत हो गई। दंपती रात को जोधपुर में शादी अटेण्ड कर अपने गांव ओसियां लौट रहा था, तब यह हादसा हुआ। पुलिस ने आज सुबह शवों का पोस्टमार्टम करवा परिजन को सुपुर्द किया। बताया जाता है उनकी कार एक ट्रक से जा भिड़ी जोकि गाजरों से लदी थी। ट्रक भी पलटी खा गया। कार के सामने नील गाय का आना बताया जाता है।

मथानिया थानाधिकारी कैलाशी ने बताया कि ओसियां के लढ्ढों का बास निवासी जितेंद्र सोनी (28) और उसकी पत्नी पायल सोनी (25) रात को जोधपुर में शादी में शामिल होकर अपने गांव की तरफ से लौट रहे थे। रात एक बजे के आस पास यह लोग जब मथानिया के उम्मेद नगर की सरहद में पहुंचे तब कार किसी नील गाय को बचाने के प्रयास में गाजर से भरे ट्रक उनकी कार से जा भिड़ी, हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को मथानिया सीएचसी पहुंचाया। आज सुबह शवों का पोस्टमार्टम करवा परिजन को सुपुर्द किया गया। थानाधिकारी कैलाशी ने बताया कि मौके से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त किया गया है। अग्रिम जांच की जा रही है। ट्रक चालक के बारे में पता लगाया जा रहा है।

कार्यालय जिला कलक्टर, जालोर (राज.)

क्रमांक / लेखा/बोली/2025/1286 दिनांकः 26/11/2025

निविदा सूचना

इच्छुक बोलीदाताओं से RRCMS प्रोजेक्ट लागू किये जाने के तहत हार्डवेयर क्रय करने हेतु प्रतिष्ठित सदभावी पंजीकृत फर्मो / व्यवसायियों / डीलरों से खुली बोली दर संविदा हेतु बोलियां दिनांक 05.12.2025 दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित अन्य विवरण राजस्थान लोक उपापन पोर्टल http//sppp.rajasthan.gov.in एवं https//eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBNCJL2526GLOB00026

अतिरिक्त
जिला कलक्टर जालोर

DIPR/C/17466/2024

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सानिवि नगर खण्ड बीकानेर

क्रमांक-2517 दिनांक-20/11/2025

Notice Inviting Bid: 23/2025-26

Bid for the Various Civil Works" are invited from interested bidders from 19.11.2025 [09:30 AM to 01.12.2025 [06:00 PM] & Open date 02.12.2025 [11:00 AM], other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://www.pwd.rajasthan.gov.in & eproc.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in of the state and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 253.55 Lakh.

UBN No.: PWD2526WSOB17340, PWD2526W50B17341, PWD2526WSOB17342, PWD2526WSOB17343, PWD2526WSOB17344

Executive Engineer PWD
City Division, Bikaner

DIPR/C/17298/2024

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

ई-बोली आमन्त्रण सूचना

इच्छुक बोली दाताओं से 36 केवी करंट ट्रांसफार्मर (0.2s क्लास) के विभिन्न अनुपात और 36 kV पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर (0.2 क्लास) (वीएन-9015002521 यूवीएन - VPN2526GLRC02279) की खरीद हेतु ऑनलाइन बोली आमंत्रित की जाती है ।

विस्तृत एनआईवी और बोली दस्तावेज / विनिर्देश वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखने एवं डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध हैं। एनआईवी का विवरण वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in/rrvpn पर उपलब्ध है।

बोली खोलने की तिथि में संशोधन की सूचना http://eproc.rajasthan.gov.in (energy.rajasthan.gov.in/rrvpn एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर ही प्रकाशित की जायेगी।

रा.रा.वि.प्र.नि. / TR-7263/2025
राज.संवाद / सी / 25 / 14650

अधीक्षण अभियन्ता (क्रय-I)

कार्यालय नगर परिषद्, ब्यावर

Tel No. 01462-258665, 257509 Email - npbeawar@gmail.com

क्रमांक / न.प.ब्या / भण्डार / 2025-26 / 9528 दिनांक 18.11.2025

ई-दर संविदा सूचना

निम्नांकित विवरणानुसार दिनांक 01.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल राजस्थान पर सेवाओं का उपापन हेतु ई दर संविदाए आमंत्रित की जाती है। ई-दर संविदा फार्म ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल राजस्थान तथा एसपीपी पोर्टल राजस्थान से डाउनलोड कर उपयोग में लेने है। कार्यालय से फार्म विक्रय नही किये जावेंगें। विस्तृत शर्ते ई-दर संविदा फार्म में संलग्न है

क्रं. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	ई दर संविदा फार्म शुल्क	ई दर संविदा प्रोसेसिंग शुल्क
1	Scanning and digitization work of Municipal Records	40,00,000	80]000	1000	500

NIB - DLB2526A8216
UBN - DLB2526SLOB24600

प्रशासक
नगर परिषद्, ब्यावर
राज.संवाद / सी / 25 / 14640

आयुक्त
नगर परिषद्, ब्यावर

Visit us: www.mpuat.ac.in; Mail ID: zdr_arsb@yahoo.com; Mo. No.: 8112207969/9414389929

कृषि अनुसंधान केन्द्र, दाहोद रोड़, बोरवट फार्म, बाँसवाड़ा (राज.) 327 001
(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)

क्रमांक: एफ( )/कृअके/2025-26/203-206 दिनांक: 24/11/2025

निविदा सूचना (2025-26)

कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाडा, के लिये कृषि कार्य हेतु पंजीकृत संवेदक / ठेकेदार से अपेक्षित अनुभव क्षमताओं के साथ मासिक कार्य / कार्यानुसार हेतु खुली निविदाएं बंद लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। पंजीकृत संवेदक / ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देनी होगी। निविदा प्रारूप, सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpuat.ac.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदा प्रारूप प्राप्ति की अन्तिम तिथि 03.12.25 प्रातः 11.00 बजे तक रहेगी। उक्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 11.30 बजे तक जमा की जाकर मध्याहन 12.00 बजे कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रारूप जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	निविदा शुल्क (रू.)
फल अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा एवं CAMSA Project में कृषि कार्य	3,92,200/-	8000/-	500/-

संभागीय निदेशक अनुसंधान

इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में भीषण आग लगी, 50 से ज्यादा दुपहिया वाहन जले

कोटा में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में भीषण आग लग गई।

- **एक साथ पहुंची चार फॉयर ब्रिगेड ने आग पर एक घंटे में काबू पा लिया**
- **शोरूम में करीब 50 से 60 इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक व स्कूटर खड़े थे, आग की चपेट में आ गए**

कोटा, (निसं)। शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके के 80 फीट रोड़ पर बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में भीषण आग लग गई। इस आग के चलते 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर व बाइक व अन्य सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। मौके पर पहुंची चार दमकल ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया।

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि आग की सूचना सुबह 7.20 बजे लगी थी। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी जिसके बाद फायर विभाग को सूचना मिली। तत्काल इस मामले में कार्रवाई करते हुए सब्जीमंडी और श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन से दमकल गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। एक साथ पहुंची चार फॉयर ब्रिगेड ने आग पर एक घंटे में काबू पा लिया। सुबह 8.30 बजे तक आग पूरी तरह से खत्म हो गई। इस शोरूम में करीब 50 से 60 इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक व स्कूटर खड़े थे। सभी आग की चपेट में आ गए। शोरूम में रखे हुए अधिकांश सामान जलकर राख हो गए।

इस मामले में प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के जरिए लगी है। आगे पूरी कार्रवाई की जा रही है।

फायर एनओसी से लेकर सभी दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा फॉयर फाईटिंग की क्या व्यवस्था थी इस मामले में भी जांच की जाएगी। राकेश व्यास ने बताया कि यह शोरूम करीब 2000 स्क्वायर फीट एरिया में दो मंजिला बना हुआ है जिसमें भूतल पर शोरूम को विजय कुमावत संचालित करते हैं। शोरूम में अलग-अलग जगह पर वाहन रखे थे। आग शोरूम के अंदर ही लगी और धीरे-धीरे पूरे शोरूम को चपेट में ले लिया। जब बाहर धुआं निकला तब स्थानीय लोगों व राहगीरों ने इसे देखा। एहतियातन पुलिस ने 80 फीट रोड़ पर कुछ देर यातायात को भी बंद रखा। इस शोरूम के ऊपर की तरफ जिम है जिसमें नुकसान नहीं हुआ है। दमकल समय पर पहुंच गई थी इसलिए आग पर काबू पा लिया गया है।

राकेश व्यास ने बताया कि अग्निशमन कर्मचारियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया। उन्होंने आग को आसपास पहुंचने से रोका। हालांकि पास के ही एक शोरूम में भी आग की लपटें पहुंच गई थी, जिसमें उन्होंने वहां पर खड़े हुए ई-रिक्शा को चपेट में ले लिया। करीब एक दर्जन के आसपास ई-रिक्शा को नुकसान पहुंचा है। इनमें से कुछ जल भी गए हैं। शेष को तत्काल बाहर निकाल लिया गया था। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई हैं।

सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर 'राष्ट्र प्रथम' को सर्वोपरि रखें युवा : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति से यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाई

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शी सोच, दृढ़ इच्छाशक्ति और साहसिक निर्णयों से भारत को एकजुट कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं से आव्हान किया कि युवा सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर 'राष्ट्र प्रथम' को सर्वोपरि रखें तथा एक मजबूत, एकजुट तथा विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। शर्मा ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमें दिया है तथा उसी आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। शर्मा ने बुधवार को अमर जवान ज्योति से सरदार150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत यमुना प्रवाह यात्रा के तहत आयोजित समारोह को संबोधित किया।

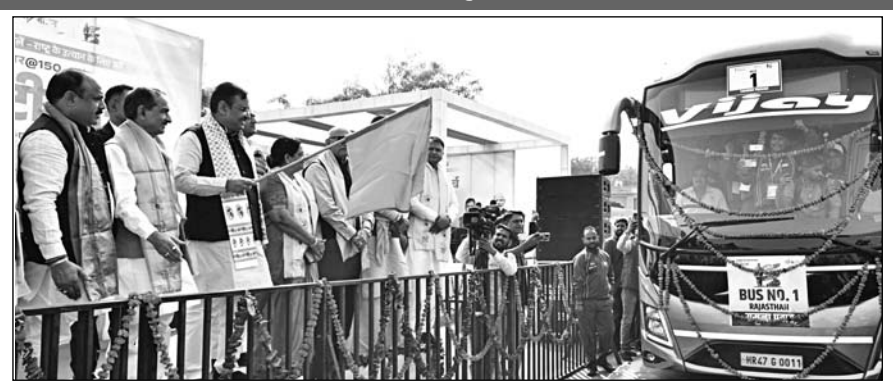

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति से यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

- **लौह पुरूष ने दूरदर्शी सोच और साहसिक निर्णयों से देश को किया एकजुट : सीएम**

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर पूरे देशभर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी के तहत यमुना प्रवाह यात्रा भी संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के तहत राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेशों से युवा जयपुर से सरदार पटेल की जन्मभूमि कमरसद तक की यात्रा करेंगे। यह यात्रा युवाओं के लिए सरदार पटेल के जीवन, संघर्ष और देशभक्ति को करीब से जानने का अवसर है। साथ ही, युवाओं को सरदार पटेल के आदर्शों और मूल्यों को समझने का प्रत्यक्ष अनुभव भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान रहा। बारडोली सत्याग्रह में उनकी प्रभावशाली भूमिका के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई।

उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और किसानों को अपने अधिकारों के लिए लडना सिखाया और सरदार पटेल जेल भी गए। लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया।

शर्मा ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिली लेकिन विभाजन का दर्द भी सहना पड़ा। उस समय देश सैकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ था। उन्होंने कहा कि देश की 562 रियासतें स्वतंत्र इकाई थी। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, दूरदर्शिता और कभी-कभी कठोरता का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक रियासत को भारत में मिलाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद तथा जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ को भारत में शामिल कराया। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया और उसे पूरा करके दिखाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। सरदार पटेल का अधूरा सपना प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर पूरा किया। प्रधानमंत्री भारत को एक सूत्र में बांध रहे हैं।

पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक आज भारत एक हो रहा है। सरदार पटेल के योगदान को सम्मान देते हुए विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में गरीब कल्याण, विकास योजनाओं, आतंकवाद-नक्सलवाद का खात्मा तथा विश्व पटल पर देश का सम्मान बढ़ने जैसे अभूतपूर्व कार्य हुए हैं।

उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत को उम्मीदों से देख रहा है तथा दुनिया के सबसे बड़े लीडर के नेतृत्व में देश नई ऊचाईयां छू रहा है।

शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन युवाओं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। युवा पीढ़ी उनके जीवन से कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, दृढ़ संकल्प, एकता तथा सादगी की पांच प्रमुख सीख ले सकती है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरदार150 यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को नमन भी किया। इस दौरान सांसद मदन राठौड़, मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, जितेन्द्र गोठवाल, गोपाल शर्मा, बालमुकुन्दाचार्य सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

एसबीए ग्रुप ने ''हडल'' का शुभारंभ किया

भारतीय व्यवसायों को वैश्विक उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए प्रमुख सहयोगी कार्यस्थल

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एसबीए ग्रुप के ''हडल'' का उद्घाटन किया। उनके साथ सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद थीं।

जयपुर। सात दशकों की अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक विशेषज्ञता वाली अग्रणी परामर्श फर्म एसबीए ने बुधवार को ''हडल'' का उद्घाटन किया, जो भारतीय व्यवसायों को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक अत्याधुनिक सहयोगी कार्यस्थल है। इसका कार्यालय 10वीं मंजिल, सिग्नेचर एलीट जे-7, गोविंद मार्ग जयपुर में है।

मुख्य अतिथि विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि हडल भारतीय व्यवसायों के बहुराष्ट्रीय संचालन में विस्तार के लिए आधार तैयार करेगा। यह पहल राजस्थान सरकार की राइजिंग राजस्थान दृष्टि में पहला ठोस कदम है। ऐसी परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत पहल को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। एसबीए के अध्यक्ष ने हडल की रणनीतिक दृष्टि को भारत भर में स्टार्टअप्स और विकास चरण के व्यवसायों के लिए एक व्यापक इनक्यूबेशन केंद्र के रूप में व्यक्त किया। हडल उद्यिमयों को प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं के साथ इष्टतम आराम प्रदान करता है। एसबीए की वैश्विक उपस्थिति का लाभ उठाते हुए, हम जयपुर के केंद्र से व्यवसायों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ फलने-फूलने में सक्षम बनाते हैं।

एसबीए ग्रुप के सीईओ अर्पित भार्गव और सीओओ राधिका शर्मा ने हडल को जयपुर और राजस्थान में बढ़ते व्यवसायों के लिए लॉन्चपैड बताया। एसबीए कंपनियों को एक ही छत के नीचे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सलाह प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों की सत्तर वर्षों की सेवा पर निर्मित, एसबीए ने एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो परामर्श, प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और पेशेवर सलाहकार सेवाओं को एकीकृत करता है। समारोह में स्वर्गीय सीए वी.एन. भार्गव, एसबीए के सह-संस्थापक के सम्मान में विश्वेश्वर सभागार का समर्पण किया गया। समारोह में सांसद मंजू शर्मा, मंत्री गौतम कुमार दक और कन्हैया लाल ने पहल की प्रशंसा की और इस परिवर्तनकारी सहयोगी स्थान के लिए एसबीए को बधाई दी।

राजस्थान को 3 प्रमुख श्रेणियों में राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड-2025 मिला

आर.सी.डी.एफ. ने लगातार दूसरे वर्ष राष्ट्रीय कीर्तिमान रचा

जयपुर (कासं)। राजस्थान ने देशभर में सर्वाधिक तीन राष्ट्रीय अवार्ड जीतकर एक बार फिर इतिहास रचा हैं। भारत सरकार ने तीनों प्रमुख श्रेणियों में राजस्थान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड-2025 से सम्मानित किया है। देशभर से प्राप्त 2081 आवेदनों में से राजस्थान को तीन श्रेणियां में अवार्ड मिलना राज्य की मजबूत डेयरी प्रणाली, नवाचार, क्षमता, उच्च गुणवत्ता और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी दक्षता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर बुधवार को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित भव्य समारोह में राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) को उत्कृष्टता के लिए दो अलग- अलग श्रेणियां में सम्मानित किया गया। केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री एस. पी. सिंह बघेल तथा जार्ज कुरियन ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवॉर्ड प्रदान किए। इस अवसर पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक एवं प्रशासक श्रुति भारद्वाज के साथ सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों के पदाधिकारी ने यह सम्मान ग्रहण किया। बेस्ट डेयरी को-ऑपरेटिव सोसायटी का अवार्ड घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति (जयपुर) को मिला। समिति को भारत सरकार द्वारा रु. 3 लाख रु., मेरिट सर्टिफिकेट और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए।

केन्द्रीय पशुपालन व डेयरी राज्यमंत्री एस. पी. सिंह बघेल तथा जार्ज कुरियन ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवॉर्ड से आरसीडीएफ को नवाजा। यह पुरस्कार प्रबंध संचालक एवं प्रशासक श्रुति भारद्वाज व जिला दुग्ध संघों के पदाधिकारियों ने ग्रहण किया।

इसी तरह बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड हर्षित झुरिया (सीकर) को मिला। उन्हें 2 लाख रु., मेरिट सर्टिफिकेट और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। हर्षित झुरिया को दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता सुधार की दिशा में किए गए नवाचारी प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इसके अलावा बेस्ट टेक्नीशियन अवार्ड विकास कुमार (हनुमानगढ़) को मिला।

राष्ट्रीय स्तर पर डेयरी क्षेत्र में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सभी विजेताओं और प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष में भी राजस्थान ने दो श्रेणियों में राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड हासिल कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी।

10 दिव्यांगों को मिलेगा सम्मान

जयपुर। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को भारतीय दिव्यांग संघ की ओर से जवाहर कला केन्द्र स्थित रंगायन सभागार में दिव्यांगों से जुड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देशभर से दिव्यांगजन अपनी कला, प्रतिभा और दक्षता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। मुख्य अतिथि राज्यपाल हरीभाऊ किशनराव बागडे होंगे।भारतीय दिव्यांग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद नारायण और राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार देवेंद्र कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी।

'गवाही तक जांच अधिकारी का रोके वेतन'

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने चंदवाजी थाने में दर्ज आपराधिक मामले में जांच अधिकारी के निचली अदालत में गवाही के लिए नहीं जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी उदय सिंह दूसरे कामों में व्यस्तता का हवाला देकर निचली अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। यह गवाही से बचने का प्रयास है और अभियोजन पक्ष गवाह पेश करने में विफल रहा है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस महानिदेशक और कोषाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जब तक अनुसंधान अधिकारी गवाही के लिए ट्रायल कोर्ट में हाजिर नहीं हो या अदालत उन्हें राहत नहीं दे, तब तक उसका वेतन और अन्य भत्ते रोक लिए जाए।

राजस्थान विधानसभा में ''वंदे मातरम् दीर्घा'' का उद्घाटन

जयपुर (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि देश का संविधान सुरक्षित है। इसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान भारत की आत्मा, भविष्य और वर्तमान है। दुनिया में भारत का संविधान ही ऐसा मजबूत संविधान है जिसके माध्यम से सत्ता का हस्तान्तरण शांतिपूर्ण तरीके से होता है। भारतीय संविधान की यह सबसे बड़ी विशेषता है।

देवनानी ने कहा कि वन्दे मातरम् केवल गीत ही नहीं है, यह मातृभूमि के प्रति समर्पण, औपनिवेशिक दमन के विरुध प्रतिरोध और स्वाधीनता की सामूहिक चेतना का प्रभावी प्रतीक है। समय के साथ यह गीत जन सभाओं और सांस्कृतिक आयोजनों में भारत के स्वतन्त्रता संग्राम की प्रेरणा शक्ति बन गया है। स्पीकर देवनानी राजस्थान विधान सभा में बुधवार को संविधान दिवस पर आयोजित युवा संवाद समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

देवनानी ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारम्भ किया। देवनानी ने इस मौके पर विधान सभा के डिजिटल म्यूजियम में उनकी पहल से निर्मित वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया। देश की विधान सभाओं में राजस्थान विधान सभा कदाचित ऐसी विधान सभा बन गई है, जहाँ वंदे मातरम् दीर्घा का निर्माण किया गया है। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सोच व परिकल्पना के अनुरूप राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के ऐतिहासिक पहलुओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। देवनानी ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम है। देश के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखे। देश के लिए जिए। अधिकारों को मांगे लेकिन कर्तव्यों के निर्वहन के दायित्व से भी मुँह ना मोडे। पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र हित का कार्य करें। भारत विश्व की महान शक्ति है। भारत विश्व गुरु है। यह सब भारतीय संविधान के कारण ही सम्भव है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि संविधान की मूल भावना में न्याय है। न्याय सभी को मिले। न्याय व्यवस्था में विश्वास करें। इसका स्वयं पालन करें और फिर दूसरों को कहे। समारोह में मौजूद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संविधान की मजबूती बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि संविधान राष्ट्र के लोगों की भावना है। स्पीकर देवनानी ने बताया कि 47 पैनलों के माध्यम से वंदे मातरम के इतिहास और इससे सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियों का दीर्घा में समावेश किया गया है। उन्होंने कहा कि सन् 1875 में अक्षय नवमी के दिन वंदे मातरम की रचना, बंकिमचन्द्र ने इसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लालगोला में लिखा, संस्कृतनिष्ठ बंगाली में लिखे गए मूल गीत के चित्र सहित विभिन्न जानकारियां आमजन, युवा, शोधार्थी और छात्र-छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा स्थित राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में वंदे मातरम् दीर्घा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना के इतिहास को नई दृष्टि से प्रस्तुत करने वाली एक प्रेरणादायी पहल है। दीर्घा बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ''वंदे मातरम् की मूल भावना को केंद्र में रखते हुए स्वदेशी आंदोलन, जन-आंदोलनों तथा क्रांतिकारियों की भूमिका को सजीव रूप में दर्शाती प्रतीत हो रही है। दीर्घा में गीत की मूल पंक्तियों, पांडुलिपि की प्रतिकृति और उस समय के राजनीतिक-सांस्कृतिक परिवेश का सुव्यवस्थित प्रदर्शन किया गया है। इससे आगंतुकों को स्वतंत्रता संग्राम के दौर की भावनाओं का अनुभव हो सकेगा। वंदे मातरम् के भावपूर्ण संगीत तथा आंदोलन से जुड़े दुर्लभ फोटोग्राफ़, पत्र, भाषण और वीडियो सामग्री भी दीर्घा में शामिल की गई है।

स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम में वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद थे।

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय के प्रवेश पथ को राजस्थान की कला, संस्कृति के अनुरूप भित्ति चित्रों के माध्यम से नये सिरे से तैयार कराया है। राजस्थान के महापुरुष, कलाकृतियां, लोक कला, लोक नृत्य, राष्ट्रीय पक्षी, राज्य पशु के साथ यहां के पारंपरिक हाथी, घोडे सहित राज्य की कला और संस्कृति को समेटे हुये भित्ति चित्रों के माध्यम से प्रवेश पथ को बनाया गया है।

राज्य में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति : डॉ. किरोडी लाल

प्रदेश में वर्तमान में 1.84 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 65 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 64 हजार मैट्रिक टन एनपीके एवं 1.53 लाख मैट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध

जयपुर (कासं)। कृषि मंत्री डॉ. किरोडी लाल ने बुधवार को राज्य में कृषकों को उर्वरको की आपूर्ति एवं आवश्यकता अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों व ब्लॉकों को चिन्हित कर प्रदेश भर में प्राथमिकता के साथ पूर्ण पारदर्शिता से उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए विभागीय अधिकारी प्रदेश भर में पूर्ण सतर्कता से कार्य कर रहे हैं।

कृषि मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने बताया कि राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रबी 2025 में अक्टूबर व नवम्बर में भारत सरकार द्वारा आवंटित 7 लाख 55 हजार मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध 01 अक्टूबर 2025 को उपलब्ध स्टॉक सहित अब तक 8 लाख 99 हजार मैट्रिक टन की उपलब्धता की गई है एवं 35 हजार मैट्रिक टन यूरिया परिवहन में है, जिसकी आपूर्ति आगामी 2 दिवसों में हो जायेगी।

- **35 हजार मैट्रिक टन यूरिया परिवहन में है, प्रदेश में फिलहाल राज्य की मांग से अधिक उर्वरकों की उपलब्धता है।**

उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख 84 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 65 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 64 हजार मैट्रिक टन एनपीके एवं 1 लाख 53 हजार मैट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध है।

वर्तमान में गत वर्ष की तुलना में फॉस्फेटिक उर्वरकों का स्टॉक 69 हजार मैट्रिक टन अधिक है। केंद्र सरकार की ओर से यूरिया, डीएपी एव अन्य उर्वरकों का राज्यों को माहवार व कम्पनीवार आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन एवं जिलों की मांग के अनुसार जिलेवार आपूर्ति योजना तैयार कर प्रदेश में उर्वरकों का वितरण पारदर्शिता से कराया जा रहा है।

प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने बताया कि कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित सिफारिशानुसार ही उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने, उर्वरकों का समान रूप से पारदर्शिता के साथ वितरण कराने और उर्वरक वितरण में अनियमित्ता बरतने वाले विक्रेताओं, जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

राजपाल ने बताया कि विभाग द्वारा राज्य में प्रत्येक उर्वरक विक्रेता के विक्रय परिसर पर उर्वरकों का वितरण व प्रभावी मोनेटरिंग किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों, कार्मिकों की नामजद ड्यूटी लगायी गई है। किसी विक्रेता के यहां कृषकों की संख्या अधिक होने पर कृषकों को पंक्तिबद्ध किया जाकर उनकी देख-रेख में उर्वरकों का वितरण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया गया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से उर्वरकों का अन्य राज्यों में परिगमन रोकने हेतु विभागीय कार्मिक एवं आवश्यकतानुसार पुलिस के सहयोग से 61 चैक पोस्ट स्थापित किये गये हैं, जिनके द्वारा नियमित निगरानी जारी है।

समय-समय पर विशेष अभियान चला कर उर्वरक वितरण में जमाखोरी, कालाबाजारी, यूरिया डायवर्जन सहित अन्य अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई है।

लो फ्लोर बस चालकों की हड़ताल समाप्त

जयपुर। जेसीटीसीएल,बगराना डिपो की लो -फ्लोर बस चालको की दो दिन से चल रहीं हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई। लो फ्लोर बसों का संचालन करने वाली निजी फर्म पारस ट्रेवल्स ने ड्राइवर यूनियन की 5 मांगों को लेकर सहमति बन गई।

इससे पहले बुधवार को बगराना डिपो के बाहर बस चालकों ने जमकर विरोध- प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि पारस ट्रेवल्स फर्म लगातार श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। ड्राइवरों को मेंटेनेंस के बिना खराब बसें चलाने को मजबूर किया जाता है। जिससे हादसे का खतरा बढता है। बीते दिनों टोंक फाटक पुलिया पर बस में लगी आग और पिछले दिनों में हुए कई हादसे इसी लापरवाही का नतीजा हैं। जिसके बाद पांच सूत्रीय मांगों को मान लिया गया। लो -फ्लोर बस चालकों ने दुर्घटना में मारे गए लो -फ्लोर बस चालक कुलदीप मीणा के परिवार को आर्थिक सहायता, ड्यूटी के दौरान लकवा ग्रस्त चालक रामजीलाल शर्मा के परिवार को आर्थिक सहायता,दोनों चालकों के वेतन, ओवरटाइम, पीएफ, ईएसआई क्लेम और पेंशन का तुरंत भुगतान करने की मांग की। जिसके बाद डिपो प्रबंधन ने बस चालकों की मांग को स्वीकार करते हुए ड्राइवरों की सैलरी में बढोतरी करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि दो दिन पहले लो -फ्लोर बस चालको ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर दी थी।

2 साल में राजस्थान ने जोड़ी 19 हजार मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता : हीरालाल नागर

जयपुर (कासं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में दो दिवसीय ग्लोबल सोलर एक्सपो-2025 का उद्घाटन किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप राजस्थान आज अक्षय एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 35 हजार 357 मेगावाट तक पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीते लगभग दो वर्षों में इस क्षमता में करीब 19 हजार मेगावाट की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2070 तक देश को नेट-जीरो के लक्ष्य की दिशा में राजस्थान पूर्ण प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहा है।

नागर ने कहा कि पीएम कुसुम योजना ने किसानों को अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता भी बनाया है। प्रदेश में इस योजना के तहत लगभग 2400 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, जिससे किसानों को दिन में भी कृषि कार्यों हेतु सस्ती एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसी दिशा में राज्य सरकार पूरी तरह समर्पित है।

प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग अजिताभ शर्मा ने कहा कि कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि कम्पोनेंट-सी में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा की असीमित संभावनाओं को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का उद्देश्य नवीन नीतियों एवं नवाचार के माध्यम से प्रदेश में सौर उत्पादन के साथ-साथ भंडारण क्षमता का भी विकास करना है। नागर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न सोलर कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे नवीन एवं अत्याधुनिक सौर उत्पादों की जानकारी ली। इस अवसर पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता, इंटरनेशनल के सीईओ आनंद गुप्ता, सौर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आगंतुक उपस्थित थे।

कस्टोडियन भूमि के वास्तविक कब्जाधारियों को विधिसम्मत अधिकार दिलाने की पहल तेज

विधायक यूनुस ख़ान के नेतृत्व में सामूहिक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

डीडवाना, (निसं)। विधानसभा क्षेत्र के विधायक यूनुस ख़ान ने शासन सचिवालय जयपुर में मुख्य सचिव राजस्थान वी. श्रीनिवास तथा शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग, डॉ. जोगाराम से मुलाकात कर उपखण्ड डीडवाना की निष्क्रान्त (कस्टोडियन) भूमि पर बसे वास्तविक कब्जाधारियों को विधिसम्मत नियमन, आवंटन एवं नामान्तकरण प्रदान करने से संबंधित विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन भी उपस्थित रहे।

विधायक यूनुस ख़ान ने मुलाकात के दौरान बताया कि डीडवाना के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में सैकड़ों परिवार पिछले कई दशकों से कस्टोडियन दर्ज भूमि पर निवास और कृषि कार्य कर रहे हैं, किंतु उन्हें अब तक कानूनी स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों ने स्वतंत्रता के बाद कठिन परिस्थितियों में घर बनाए, भूमि को उपजाऊ बनाया, व्यवस्थित रूप से कर अदा किए और सामाजिक रूप से स्वयं को स्थापित किया, फिर भी राजस्व

- **कस्टोडियन भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे पात्र परिवारों को राहत दिलाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी सरकार : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास**

अभिलेखों में भूमि कस्टोडियन के रूप में दर्ज रहने के कारण आज वे कानूनी अनिश्चितता और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से ऐसे परिवारों को उनका वास्तविक और विधिसम्मत अधिकार दिलाने के लिए त्वरित एवं ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया कि डीडवाना-कुचामन जिला कलेक्टर को आवश्यक दिशा-निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी और कस्टोडियन भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे पात्र परिवारों को राहत दिलाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी।

शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने भी विस्तृत चर्चा में बताया कि विभाग कस्टोडियन भूमि संबंधी प्रकरणों के व्यवस्थित निस्तारण के लिए विशेष समीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है, तथा डीडवाना क्षेत्र जैसे प्रभावित इलाकों में जिला स्तरीय समिति गठित कर सर्वे व सत्यापन कार्य तेज किए जाएंगे। उन्होंने नियमन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में भी आश्वासन दिया।

ज्ञापन के साथ विधायक यूनुस ख़ान ने निष्क्रान्त संपत्ति की ऐतिहासिक एवं कानूनी पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान पाकिस्तान गए परिवारों की संपत्तियों को भारत सरकार ने 'निष्क्रान्त संपत्ति' घोषित कर कस्टोडियन विभाग को सुपुर्द किया था। इसके बाद राजस्थान सरकार ने 1963 और 1970 के भू-राजस्व नियमों में इनके स्थायी आवंटन के लिए प्रावधान किए। भारत सरकार के कैबिनेट निर्णय 69/2008 के अनुसार अप्रयुक्त निष्क्रान्त भूमि को 'सिवायचक' दर्ज करने के निर्देश दिए गए, जिनके अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में जारी आदेशों के अनुसार इन भूमियों को सिवायचक में दर्ज किया गया। अतिरिक्त रूप से, जिला कलक्टर, नागौर द्वारा दिनांक 11.04.2011 को पारित आदेश में डीडवाना उपखण्ड की समस्त कस्टोडियन भूमि को सिवायचक में परिवर्तित किया जा चुका है। प्रदेश के अनेक जिलों में अब तक हजारों काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिए जा चुके हैं, परंतु डीडवाना के पात्र परिवार अभी भी इस प्रक्रिया से वंचित हैं।

विधायक यूनुस ख़ान ने स्पष्ट रूप से कहा कि उपखण्ड डीडवाना में विशेष सर्वे अभियान चलाकर कस्टोडियन भूमि की संपूर्ण पहचान की जानी चाहिए और वास्तविक कब्जाधारियों को नियमन व आवंटन की विधिक प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पूर्व में आवंटन या पंजीयन हुआ है, वहां मौजूद अभिलेखीय विसंगतियों को दूर कर पात्र व्यक्तियों को वैध पट्टे और खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाएं तथा संपूर्ण प्रक्रिया में पंचायतों, नगर निकायों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने विधायक यूनुस ख़ान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों से लंबित इस गंभीर समस्या को सरकार के सर्वोच्च स्तर पर मजबूती से उठाकर प्रभावित परिवारों के लिए आशा की किरण जगाई है। उन्होंने कहा कि विधायक के प्रयासों से अब कस्टोडियन भूमि विवाद के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होने की वास्तविक संभावनाएं बनी हैं।

अंत में विधायक यूनुस ख़ान ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन मिलकर इस विषय पर शीघ्र, पारदर्शी और मानवीय समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक डीडवाना क्षेत्र के प्रत्येक पात्र परिवार को उनका विधिसम्मत अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक यह प्रयास लगातार जारी रहेगा।

नकबजनी की वारदात का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी अपने हैंड बैग में हमेशा ताला तोड़ने के लिए फोल्डिंग सरिया रखकर चलता था

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाजार नम्बर दो स्थित दुकान में हुई नकबजनी की वारदात का राजकॉप एप की मदद से खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल शातिर नकबजन पवन मीणा निवासी बड़ा ऊँचा, थाना छबड़ा (जिला बारां) को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में नकबजनी और लूट की 27 वारदातों में चालानशुदा रह चुका है। आरोपी अपने हैंड बैग में हमेशा ताला तोड़ने के लिए फोल्डिंग सरिया रखकर चलता था।

पुलिस ने शातिर नकबजन पवन मीणा को गिरफ्तार किया।

जानकारी के अनुसार 18 नवंबर को परमानंद गुरनानी निवासी कुमुद विहार ने रिपोर्ट दी कि उनकी दुकान-हीरा ट्रेडर्स, बाजार नंबर दो का शटर टूटा हुआ मिला है। दुकान के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सुबह 5:15 बजे एक बदमाश गले का ताला तोड़कर 2,45,000 रुपये चोरी कर ले गया। इस रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की गई। कोतवाली पुलिस की विशेष टीम ने पड़ताल व सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया।

एक फुटेज में स्पष्ट चेहरा दिखने पर उसे राजकॉप ऐप में फोटो मैच किया गया, जिसमें आरोपी की पहचान पवन मीणा के रूप में हो गई। पोर्टल पर सर्च करने पर पता चला कि आरोपी राजस्थान के लगभग सभी जिला मुख्यालयों के रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में

- **प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में नकबजनी और लूट की 27 वारदातों में चालानशुदा रह चुका है आरोपी**

नकबजनी और अकेली महिलाओं से लूट करने के मामलों में 27 बार चालानशुदा है। आरोपी के गांव में तलाश की गई, जहां यह सामने आया कि वह वर्षों से वहां नहीं गया। उसके तरीके को देखते हुए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर रेलवे स्टेशनों पर निगरानी शुरू की गई।

निगरानी के दौरान आरोपी की पहचान कांस्टेबल संजय जीनगर और कांस्टेबल भूपेंद्र गिरी ने की। रैकी के दौरान पवन मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी में इस्तेमाल फोल्डिंग सरिया बरामद कर ली। अनुसंधान जारी है।

अपराध का तरीका :- पवन मीणा लगातार एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन पर घूमता रहता था। नशे की लत और शौक पूरा करने के लिए वह रात को रेलवे स्टेशन के आसपास दुकानों की रैकी करता और सुबह जल्दी वारदात अंजाम देकर बस या ट्रेन से दूसरे जिले में भाग जाता था। वह लगातार ठिकाने बदलता रहता था।

एनडीपीएस मामले में फरार दो इनामी वांछित गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की सदर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में एक साल से फरार चल रहे 10-10 हजार के दो इनामी वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

- **पुलिस ने दोनों पर 10-10 हजार के इनाम की घोषणा कर रखी थी**

पुलिस ने एनडीपीएस मामले में दो इनामी वांछितों को गिरफ्तार किया।

जानकारी के अनुसार 12 नवंबर 2024 को तत्कालीन थानाधिकारी उगमाराम गश्त कर रहे थे। इस दौरान बड़ा महुआ से गोवर्धनपुरा जाने वाले रोड पर एक सफेद रंग की कार को डिटेन किया, जिसका चालक मौके से फरार हो गया था। नियमानुसार मौके पर कार की तलाशी कार्रवाई की तो उक्त कर में चार प्लास्टिक कट्टों में 62 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा-चूरा मिला। जिसे प्रकरण में जप्त किया घटना का प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने मौके से फरार आरोपी की तलाश शुरू की। वाहन में मिले वाहन बीमा के कागजात के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की गई। मुखबिर के जरिए और तकनीकी सहायता से अज्ञात आरोपियों की तलाश करते हुए पुलिस ने आरोपी गोविंद पुत्र मांगीलाल गुर्जर एवं प्रकाश पुत्र भोजराज गुर्जर निवासी बड़ी धनगांव थाना सिंगोली एमपी को घटना में शरीक होना पाया और दोनों आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई के नेतृत्व में टीम ने एक साल से फरार चल रहे आरोपी गोविंद और प्रकाश गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है।

अवैध बजरी खनन का स्टॉक जब्त, दो गिरफ्तार

बौंली थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन स्टॉक जब्त कर दो चालकों को गिरफ्तार किया।

बौंली-बामनवास, (निसं)। सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध बजरी खनन व स्टॉक पर कार्रवाई करते हुए बौंली थाना पुलिस ने एक लोडर, एक पिकअप केन्ट्रा व आठ टन बजरी स्टॉक को जब्त कर दो चालकों को गिरफ्तार किया है।

- **एक लोडर, एक पिकअप केन्ट्रा व आठ टन बजरी स्टॉक जब्त**

बौंली सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हैड कांस्टेबल जयदेव सिंह ने मय टीम के 8 लाइन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे टोलटैक्स बौंली के पास खाली जगह में अवैध बजरी स्टॉक कर बजरी को लोडर की सहायता से भरते हुए एक लोडर व एक पिकअप कैंट्रा व 80 टन अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त कर लोडर चालक मुकून गुर्जर निवासी गुडला नदी व मुरारी लाल मीणा पिकअप केंट्रा चालक निवासी झनूण को गिरफ्तार किया। सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि ये साधन लोडर व पिकअप केंट्रा प्रवीण गोयल निवासी बौंली के नाम पर है, गोपनीय जानकारी मिली कि प्रवीण द्वारा 8 लाइन एक्सप्रेस-वे के पास खाली पड़ी जमीन में टोलकर्मी फिरोज गद्दी निवासी भारजा नदी थाना मलारना डूंगर द्वारा चोरी छुपे अवैध बजरी का स्टॉक करवाया जाता था एवं अवैध बजरी के स्टॉक को लालसोट बड़ का पाड़ा, जमात लालसोट में बेचा जा रहा है।

इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक मुकून गुर्जर व मुरारी लाल मीणा को मौके से गिरफ्तार कर लिया एवं अन्य आरोपी प्रवीण गोयल व टोलकर्मी फिरोज गद्दी निवासी भारजा नदी थाना मलारना डूंगर की तलाश जारी है।

सरकारी स्कूलों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट की नहीं मिली राशि

कहीं संस्था प्रधान की जेब, कहीं शाला विकास कोष से जमा हो रहे स्कूलों में बिजली-पानी बिल

बीकानेर, (निसं)। सरकारी स्कूलों में सामान्य शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों सहित भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट का प्रावधान है। नियमों के मुताबिक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से सरकारी स्कूलों को मिलने वाले इस बजट की 70 प्रतिशत राशि दिसंबर माह तक खर्च करने का प्रावधान है। वर्तमान शिक्षा सत्र में हालात यह है कि आधा सत्र भी जाने के बाद भी जिले के 725 उच्च माध्यमिक स्कूलों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट का एक रुपया भी नहीं मिला है। हालत यह है कि संस्था प्रधानों को अपनी जेब से या फिर शाला विकास कोष से बिजली-पानी के बिल सहित न्यूज पेपर और स्टेशनरी भुगतान करना पड़ रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों में होने वाले व्यय को लेकर संस्था प्रधान परेशान हैं। सरकारी स्कूलों में जमा राशि से अबकी बार दीपावली के पर्व पर सरकारी स्कूलों का रंग रोगन एवं छोटा-मोटा मरम्मत का कार्य करवाने में खर्च हो गई। जिसके कारण सरकारी स्कूलों के संचालन के लिए कई कार्य अधर में लटके हुए हैं या संस्था प्रधान एवं शिक्षक अभी अपने जेब से राशि खर्च कर रहे हैं।

नामांकन के आधार पर सरकारी स्कूलों में कंपोजिट ग्रांट की राशि निर्धारित है। इस राशि से स्कूल की स्वच्छता, बच्चों के लिए पानी, चौक, डस्टर आदि की व्यवस्था की जाती है। अब तक केवल महात्मा गांधी स्कूल सहित प्राथमिक के 50 प्रतिशत स्कूलों में ही राशि उपलब्ध कराई गई है, जबकि उच्च माध्यमिक स्कूलों को ग्रांट राशि नहीं मिली है।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से बीकानेर जिले में संचालित प्रारंभिक शिक्षा के 1485 स्कूलों को 50 प्रतिशत राशि के तहत दो किस्तों में लगभग 1.57 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। जबकि 725 उच्च माध्यमिक स्कूलों को 6 महीने बाद भी बजट की प्रथम किस्त का भी भुगतान नहीं हुआ है।

मालखाने में रखी गाड़ियों से पार्ट्स चुराने का प्रयास, तीन गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शहर के रातानाड़ा पुलिस थाने की नई बिल्डिंग निर्माणाधीन है। हॉस्टल नंबर 3 के पास में ही इसका निर्माण कार्य चल रहा है। रातानाडा पुलिस द्वारा विभिन्न मदों में जब्त की गई गाड़ियां नई बिल्डिंग के पास में मालखाना बनाकर रखी गई है। मंगलवार की रात को तीन शख्स वहां पर चोरी की नीयत से आए और गाड़ियों के पार्ट्स आदि चोरी का प्रयास करने लगे। पुलिस गश्त करते मालखाने की तरफ पहुंची तब तीन शख्स पुलिस को देख कर भागने लगे, फिर उन्हें मौके पर पकड़ा गया। उनके पास में हथौड़ी, लगिया-सरिया और कुछ नकली चाबियां मिली। बाद में उनका फोटो मिलान आदि किया तो पूर्व के नकबजन निकले। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, अग्रिम जांच की जा रही है।

- **हथौड़ी, लगिया-सरिया और कुछ नकली चाबियां मिली, आरोपियों का फोटो मिलान आदि किया तो पूर्व के नकबजन निकले**
- **आरोपियों का क्राइम रिकार्ड देखा तो पता लगा कि इनके खिलाफ पहले से ही चोरी के प्रकरण दर्ज है**

एसआई जेठाराम ने बताया कि हॉस्टल नंबर 3 के पीछे रातानाडा थाने की नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। थाना पुलिस द्वारा जब्त की गई कई गाड़ियों को पास में ही एक मालखाना बनाकर रखा हुआ है। रात आठ बजे वे गश्त करते हुए पहुंचे तब तीन संदिग्ध युवकों रातानाडा सांसी कॉलोनी पांच बत्ती निवासी किशन उर्फ बुधिया पुत्र चंपालाल सांसी, सुल्तान पुत्र जवानाराम एवं बज्गी खाना सांसी कॉलोनी राहुल पुत्र शंकरलाल को पकड़ा गया। उनके पास में चोरी करने लायक हथियार मिले। इनके पास में हथौड़ी, लगिया-सरिया और दो तीन नकली चाबियां मिली। पूछताछ में सामने आया कि यह लोग मालखाने में रखी गाड़ियों से पार्ट्स चुराने आए थे। तीनों पैदल ही थे। आरोपियों की पहचान के लिए क्राइम रिकार्ड देखा तो पता लगा कि इनके खिलाफ पहले से ही चोरी के प्रकरण दर्ज है, जिस पर गिरफ्तार कर लिया।

संविधान दिवस पर गोष्ठी आयोजित

बूंदी, (निसं)। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को कृषि विज्ञान केंद्र में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें केन्द्र के कीट वैज्ञानिक प्रोफेसर हरीश वर्मा ने संविधान उद्देशिका का वाचन किया।

उन्होंने बताया कि संविधान दिवस का उद्देश्य संविधान की सोच, संवैधानिक सिद्धांतों और नागरिक कत्तर्व्यों के प्रति जन-जागरुकता बढ़ाना है। संविधान केवल सरकार का ढांचा तय नहीं करता, बल्कि नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और गरिमा की भी रक्षा करता हैं। यह दिवस हमें लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और संवैधानिक मूल्यों को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देता है। संविधान दिवस हमें यह सीख देता है कि भले ही लोकतंत्र मतपत्र से बनता है, परन्तु हमारा देश जागरुकता, कत्तर्व्यपरायणता और संवैधानिक मूल्यों से चलता हैं। इस दौरान केन्द्र के फार्म मेनेजर महेन्द्र चौधरी, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता डॉ. दीपक कुमार, विकास ताखर, लोकेश प्रजापत, विजेन्द्र वर्मा एवं रामप्रसाद मौजूद रहे।

समर्थन मूल्य पर सोयाबीन व उड़द की खरीद शुरु

बूंदी, (निसं)। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर सोयाबीन एवं उड़द खरीद के लिए बून्दी, हिण्डोली, के. पाटन (कापरेन, सुमेरगंजमण्डी), नैनवाँ (देई) में क्रय विक्रय सहकारी समितियों में एवं खटकड़, भैरूपुरा औझा, अरनेठा, बसोली, गोठड़ा, पेंच की बावड़ी, जरखोदा व करवर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कुल 13 क्रय केन्द्र जिले में स्थापित किये गये हैं। सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार मुकेश मोहन गर्ग ने बताया कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 रू. एवं उड़द का समर्थन मूल्य 7800 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित है। 24 नवम्बर से खरीद शुरू हो चुकी है, खरीद प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए राजफैड जयपुर द्वारा पंजीकृत किसानों को अपनी जिंस निर्धारित दिनांक को तुलवाने के लिए सूचित किया जाता हैं। किसान अपनी जिंस (एफ.ए.क्यू. मापदण्ड अनुसार) खरीद केन्द्र पर निर्धारित दिनांक को ही विक्रय करें। यदि किसान किसी कारणवश निर्धारित दिनांक को क्रय केन्द्र पर अपनी जिन्स विक्रय नहीं कर पाता है, तो वह 10 दिवस की अवधि में अपनी जिन्स कभी भी तुलवा सकता है।

प्रजापति समाज के सात जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

शाहपुरा, (निसं)। त्रिवेणीधाम में श्रीयादे माता प्रजापति विकास समिति त्रिवेणी धाम शाहपुरा के तत्वावधान में खोजीद्वाराचार्य रामरिछपालदास महाराज व प्रहलाददास महाराज के सान्निध्य में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम उज्जैन धाम के सिद्धिगिरि महाराज, भाजपा पूर्व प्रदेश मंत्री सुधा कुमावत, अमृत माटी इंडिया ट्रस्ट के चेयरमैन डॉ. अंजनी किरोडीवाल, भाजपा नेता उपेन यादव, विधायक मनीष यादव, पंजाब के भाजपा प्रदेश मंत्री राजेंद्र, गंगानगर के राजीव, भामाशाह गौरीशंकर, कैलाशचंद्र, पूर्व सरपंच बल्लूराम कुम्हार, डॉ.भोजराज कुमावत अतिथि रहे। तोरण व वरमाला की रस्म के बाद गायत्री परिवार की टीम थानाराम सेपट व बल्लूराम कुम्हार के नेतृत्व में सदस्यों ने विधि विधानपूर्वक सात जोड़ों का पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न करवाया।

समारोह के दौरान अतिथियों ने कहा कि समाज उत्थान में सामूहिक विवाह सम्मेलन महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देना चाहिए। फिजूल खर्ची के साथ-साथ समाज के कमजोर लोगों को संबल मिलता है। इस

सम्मेलन में नवविवाहित जोड़ों का पाणीग्रहण संस्कार सम्पन्न कराया।

दौरान समिति अध्यक्ष संतुलाल, कालूराम माचीवाल, सुवालाल, मातादीन, कालूराम दुहारिया, शंकरलाल, बनवारी, सुरेंद्र कुमार, रमेश, हंसराज, राकेश, रोहिताश, भागीरथमल, रामचंद्र, मुकेश, पूर्व पार्षद पूजा देवी, सजना देवी, मोहन, देवी सहाय, आदित्य, किशनलाल, आदि ने अतिथियों व भामाशाहों का सम्मान किया। अतिथियों ने वर वधु को सुखी दाम्पत्य का आशीर्वाद प्रदान किया। समारोह में प्रजापति समाज समिति अहमदाबाद, बडौदा, भावनगर, मेहसाना, अलवर समिति पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में समाजबंधुओं ने भाग लिया।

- **श्रीयादे माता प्रजापति विकास समिति त्रिवेणीधाम का सामूहिक विवाह सम्मेलन सम्पन्न**

समिति एवं भामाशाहों द्वारा वर वधु को विवाह सम्मेलन में बैड, अलमारी, सिलाई मशीन, एलईडी टीवी, मिक्सी, कूलर, पंखा, बर्तन, आभूषण, घड़ी सहित विभिन्न प्रकार का सामान उपहार स्वरूप भेंट किया। महिलाओं ने वधुओं को एक-एक साड़ी कन्यादान स्वरूप भेंट की।

आजेएस भर्ती में उम्र में छूट को लेकर दाखिल याचिका खारिज

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आजेएस भर्ती में उम्र में छूट को लेकर दाखिल की गई याचिका को अब खारिज कर दिया है। उसे औचित्यहीन बताया गया। याचिकाकर्ता छूट मांग कर भूल गया, इस बीच सात साल में कई न्यायाधीश बदल गए।

- **न्यायिक सेवा भर्ती में उम्र की छूट मांगकर भूल गया याचिकाकर्ता, जस्टिस बदलते रहे, कोर्ट ने केस खारिज किया**

राजस्थान न्यायिक सेवा (आजेएस) भर्ती में केंद्रीय कर्मचारियों को उम्र में छूट देने की मांग से जुड़े इस मामले में जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने 10 साल पुरानी इस याचिका (ललित कुमार बनाम रजिस्ट्रार जनरल) को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि समय बीतने के साथ अब इसका कोई औचित्य नहीं बचा है। मामले की शुरुआत 2015 में हुई थी। जोधपुर निवासी ललित कुमार रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्यरत थे। ललित कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका सपना न्यायिक अधिकारी बनने का था, लेकिन उनकी उम्र आड़े आ रही थी। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क था कि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम-2010 के नियम-17 के तहत राज्य सरकार, पंचायत समिति, जिला परिषद और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक (5 साल की छूट) का लाभ दिया जाता है। वकील ने सवाल उठाया कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी भी उसी तरह का प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। फिर उनके साथ भेदभाव क्यों? वकील ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन बताया था और मांग की थी कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों के समान छूट मिलनी चाहिए।

उस समय हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जवाब दिया गया था कि नियम बनाने का अधिकार नियोक्ता का है। उन्होंने तर्क दिया था कि आयु में छूट एक रियायत है, इसे अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। प्रशासन का कहना था कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए स्वतंत्र है और यह जरूरी नहीं कि वही लाभ केंद्र के कर्मचारियों को भी दिया जाए।

इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू 25 अगस्त 2015 का वह आदेश है, जिसने हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें जगा दी थीं। तत्कालीन जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस जयश्री ठाकुर की डिवीजन बेंच ने ललित कुमार को अंतरिम आदेश के तहत परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। जब रिजल्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने खोला गया तो पता चला कि ललित कुमार प्रीलिम्स (प्रारंभिक परीक्षा) की कट-ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे।

कोर्ट की इतनी गंभीरता के बावजूद याचिकाकर्ता ने केस की पैरवी करना छोड़ दिया। इस केस के ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड गवाह हैं कि कैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा खुद याचिकाकर्ता की अनदेखी से समय की भेंट चढ़ गया। याचिकाकर्ता के वकील की उपस्थिति आखिरी बार 27 नवंबर 2018 के आदेश में दर्ज है।

यह एक बड़ी जीत है, ख़ासतौर पर ऐसी स्थिति में जब मैं पिछले कुछ महीनों से खेल से बाहर थे। भारत में मिली यह जीत खास है।

– टेम्बा बवुमा

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान, भारत पर मिली ऐतिहासिक जीत पर बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी

ऋषभ पंत

भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने बुधवार को दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली 408 रनों मिली हार पर कहा कि एक खिलाड़ी और टीम के तौर पर हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाये। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलु जमी पर टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय कप्तान पंत ने कहा, "यह निराशाजनक है लेकिन एक टीम के तौर पर हमें बेहतर रहना होगा। विपक्षी टीम को भी श्रेय जाता है जिस तरह से उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली। दक्षिण अफ्रीका की टीम निश्चित तौर पर हावी रही लेकिन घर पर खेलते हुए भी आप विपक्षी टीम को हल्के में नहीं ले सकते।

क्या आप जानते हैं ?... टेम्बा बावुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की टीम ने अब से करीब 31 साल पुराना ऑस्ट्रेलियाई टीम का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया।

हार की जिम्मेदारी सभी को लेनी चाहिए : गंभीर

गुवाहाटी, 26 नवंबर। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से सीरीज हार के बाद आलोचनाओं के बीच कहा कि इस हार की जिम्मेदारी सभी को लेनी चाहिए। आज यहां दूसरे टेस्ट में भारत की 408 रन से हार के बाद उनके भविष्य को लेकर गंभीर ने कहा, यह बीसीसीआई को तय करना है। मैंने पहले भी यह कहा है, भारतीय क्रिकेट जरूरी है, मैं जरूरी नहीं हूं। मैं वही आदमी हूं जिसने इंग्लैंड में नतीजे हासिल किए, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता। यह एक ऐसी टीम है जो सीख रही है। हार को सबकी कमियों बताते हुए गंभीर ने कहा कि तीसरे दिन भारत का 95/1 से 122/7 पर आना और मजबूत एग्जिक्यूशन की जरूरत को दिखाता है। उन्होंने कहा, गलती सबकी है, सबसे पहले मैं। 95/1 से 122/7 तक जाना मंज़ूर नहीं है। आप किसी एक इंसान या किसी खास शॉट को दोष नहीं दे सकते। गलती सबकी है। मैंने कभी किसी एक इंसान को दोष नहीं दिया और आगे भी ऐसा नहीं करूंगा।

उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको सबसे तेज़-तर्रार और टैलेंटेड क्रिकेटरों की आवश्यकता नहीं है। हमें कम स्किल वाले मजबूत लोगों की जरूरत है। वे अच्छे टेस्ट क्रिकेटर बनते हैं। उन्होंने पूरे देश में रेड-बॉल क्रिकेट को प्राथमिकता देने में बदलाव लाने की अपील करते हुए कहा, अगर आप सच में टेस्ट क्रिकेट को लेकर सीरियस हैं, तो टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देना शुरू करें। सबके प्रयास की जरूरत है। आप केवल खिलाड़ियों या किसी खास इंसान को दोष नहीं दे सकते। वहीं भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच श्रीकांत ने गंभीर पर बहुत अधिक प्रयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि चयन में लगातार बदलाव से टीम की स्टेबिलिटी खत्म हो गई है।

द. अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत, भारत का टेस्ट सीरीज में किया सुपड़ा साफ

गुवाहाटी, 26 नवम्बर। साइमन हार्मर (छह विकेट) के दमदार प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन बुधवार को भारतीय टीम को दूसरी पारी में 63.5 आवर में 140 रन पर ढ़ेर कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए दो मैचों की सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। इससे पहले हार्मर की घातक गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत का चायकाल के समय तक 90 के स्कोर पर पांच विकेट कर दिया था।

चायकाल के बाद भारत का छठा विकेट साई सुदर्शन के रूप में गिरा। उन्होंने 139 गेंदों में एक चौके की मदद से 14 रन बनाये। वॉशिंगटन सुदंर 44 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुये। 62वां ओवर कर रहे केशव महाराज की पहली गेंद पर छक्का लगाकर रवींद्र जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अगले ही ओवर में हार्मर, नीतीश कुमार रेड्डी को बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटा दिया। इसी के साथ छठी सफलता हार्मर के नाम रहीं। 64वें ओवर की पहली गेंद पर केशव महाराज ने रवींद्र जडेजा को आउट कर भारत को नौवां झटका दिया। रवींद्र जडेजा ने 87 गेंदों में चार चौके और दो छक्के लगाते हुए 54 रनों की पारी खेली। इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर महाराज ने को आउटकर 140 के स्कोर पर भारतीय पारी का अंत कर दिया।

पहले टेस्ट में टेम्बा बवुमा ने अर्धशतकीय पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई तो वहीं गुवाहाटी टेस्ट में पारी लड़खड़ाने के बाद मुथुसामी और यानसन ने दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े स्कोर पर पहुंचा और दोनों ही मैचों में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजो विशेषकर यानसन और हार्मर ने भारतीय बल्लेबाज़ों की नाक में दम कर रख दिया और एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत हासिल कर ली।न्यूजीलैंड के बाद अब दक्षिण अफ्रीका ने भारत का घर पर सूपड़ा साफ कर दिया।

हार्मर ने भारत में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे अधिक टेस्ट विकेट लिए हैं, उन्होंने डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है । बिना कोई टेस्ट हारे कप्तान के तौर पर सबसे अधिक टेस्ट जीत - बावुमा 12 मैचों में 11 जीत के साथ सबसे आगे हैं, वह माइक ब्लेयरली के साथ थे जिन्होंने इससे पहले 15 में से 10 जीत हासिल की थीं।

दक्षिण अफ्रीका के लिए साइमन हार्मर ने 23 ओवर में 37 रन देकर छह विकेट लिये। केशव महाराज को दो विकेट मिले। सेनुरन मुतुसामी और मार्का यानसन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पूर्व भारत ने आज सुबह कल के 27 रन पर दो विकेट से आगे खेलना शुरु किया। पहले सत्र की शुरुआत में 24वें ओवर में साइमन हार्मर ने कुलदीप यादव (पांच) को बोल्ड कर भारत को तीसरा झटका दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने ध्रुव जुरेल (दो) को एडन मारक्रम के हाथों कैच आउट भारत के मैच ड्रा कराने की उम्मीदों को करारा झटका दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान ऋषभ पंत ने साई सुदर्शन के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया और इसी दौरान एक चौका और एक छ्क्का लगाते हुए तेज शुरुआत का संकेत भी दिया।

32वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्मर ने पंत को मारक्रम के हाथों कैच आउट कराकर भारत को पांचवां झटका दिया। पंत ने 16 गेंदों मे 13 रन बनाये। कुछ देर पिच पर जमने के बाद रवींद्र जडेजा ने भी हाथ खोला और 43वां शुरु कर रहे केशव महाराज की पहली ही गेंद छक्का जड़ा दिया। भारत ने चायकाल तक पांच विकेट पर 90 रन बनाये और साई सुदर्शन 138 गेंदों में (14) तथा रवींद्र जडेजा 40 गेंदों में (30) मैच बचाने के लिए संघर्ष करते दिखे।

जयपुर मिलिट्री स्टेशन में स्पेशल ओलंपिक्स स्टेट गेम्स एथलेटिक्स का भव्य आगाज

300 से ज्यादा एथलीटों ने लिया हिस्सा

जयपुर, 26 नवंबर। जयपुर मिलिट्री स्टेशन के गांदीव स्टेडियम में बुधवार को स्पेशल ओलंपिक्स स्टेट गेम्स एथलेटिक्स-2025 का भव्य आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम सप्त शक्ति आर्मी विमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन और स्पेशल ओलंपिक्स भारत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत प्रदेशभर से आए स्पेशल एथलीटों के आकर्षक मार्च-पास्ट से हुई। इसके बाद बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बैंड डिस्प्ले और टॉर्च रिले के जरिए दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि स्पेशल ओलंपिक्स विशेष बच्चों की छिपी प्रतिभा को सामने लाने का सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि आज हुए से स्पेशल ओलंपिक्स से जुड़े बच्चों को आगे बढ्ने के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने अभिभावकों और समाज से अपील की कि विशेष बच्चों को अधिक से अधिक मौके दें। क्योंकि ये खेल, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं।

राजस्थान से 300 से ज्यादा बच्चे इस स्टेट गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। यहां से चयनित एथलीट नेशनल ओलंपिक्स में भाग लेंगे और उसके बाद चिली में होने वाले इंटरनेशनल ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर पाएंगे। साथ ही, उन्होंने कहा कि से प्रतिभाशाली बच्चों को नई दिशा और पहचान मिलेगी। सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह ने दिया कुमारी और डॉ. नड्डा का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के आत्मविश्वास को बढ्ाते हैं और इन्हें निरंतर आयोजित किया जाना चाहिए।

पीपीसी पोलो ग्राउंड पर पहला मैच रामबाग पोलो ओर ऑल स्टार पोलो टीम के बीच और दूसरा मैच रामबाग पोलो ग्राउंड पर चूंडा पोलो टीम एवं जयपुर पोलो टीम के बीच मैच खेला गया।

राजस्थान यूनाइटेड ने 41वें गवर्नर गोल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई

गंगटोक, 26 नवंबर। राजस्थान यूनाइटेड ने ऐतिहासिक पालजोर स्टेडियम में खेले गए एक रोमांचक सेमीफाइनल में सिक्किम ड्रैगन्स को 3-2 से हराकर 41वें गवर्नर गोल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। भावनाओं, जुझारूपन और आखिरी मिनट के ड्रामा से भरे इस मैच में, ने प्रतिष्ठित फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए शानदार मानसिकता का प्रदर्शन किया।

पहला गोल स्थानीय हीरो, नोविन गुरुंग ने किया, जो राजस्थान टीम में सिक्किम के एकमात्र खिलाड़ी हैं। अपने घरेलू मैदान पर स्थानीय टीम के खिलाफ गोल करना इस पल को और भी खास बनाता है। मिडफील्डर नाओबा मेइतेई ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही एक शानदार फिनिश के साथ बढ़त को और बढ़ा दिया। सिक्किम ड्रैगन्स के देर से दबाव के साथ, मैच एक्स्ट्रा टाइम की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी पेड्रो एस्ट्राय ने 90 6 मिनट में एक सनसनीखेज गोल करके आखिरी सेकंड में को जीत दिला दी।

राजस्थान यूनाइटेड के कोच विकास रावत ने एक बयान दिया

यह जीत टीम की सामूहिक भूख को दिखाती है। हम अनुशासित रहे, दबाव में भी डटे रहे और अपनी पहचान पर भरोसा रखा। इस माहौल में सेमीफाइनल कभी आसान नहीं होता, लेकिन लड़कों ने इसे समझदारी से संभाला। अब हम उसी विश्वास और मकसद के साथ फाइनल की तैयारी करेंगे।

चेयरमैन केके टाक ने भी टीम को बधाई दी

गवर्नर गोल्ड कप के फाइनल में पहुंचना राजस्थान यूनाइटेड के लिए गर्व का पल है। यह सालों के विकास, हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और क्लब के अंदर बढ़ रही एक मजबूत फुटबॉल संस्कृति को दिखाता है। पूरे भारत के फैंस का सपोर्ट हमें एनर्जी देता है, और हम उसी एनर्जी के साथ फाइनल में जाएंगे। कैप्टन भाबिंद्र मल्ला ने कहा आज हर खिलाड़ी ने अपना सब कुछ दे दिया। जब मैच में टेंशन बढ़ गई, तब भी हम एक टीम की तरह साथ खड़े रहे। हमें फाइनल में पहुंचने पर गर्व है, लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हम ट्रॉफी के लिए और घर पर हमारा सपोर्ट करने वाले सभी लोगों के लिए लड़ेंगे।

स्पेशल हाईलाइट - अपनी धरती पर एक गोल

पहले गोल करने वाले, सिक्किम के रहने वाले नोविन गुरुंग को लोकल भीड़ के कुछ हिस्सों से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अपनी होम टर्फ पर उनका गोल एक सिंबॉलिक पल था, जहां जुनून और गर्व एक साथ मिले, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की यात्रा में योगदान दिया और उस जगह का प्रतिनिधित्व किया जहां वह पले-बढ़े थे। राजस्थान यूनाइटेड 41वें गवर्नर गोल्ड कप के फाइनल में खेलेगा। मैच की डिटेल्स सिक्किम द्वारा अनाउंस की जाएंगी।

एडन मारक्रम एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक कैच लेने वाले पहले द. अफ्रीका खिलाड़ी

गुवाहाटी, 26 नवंबर। एडन मारक्रम ने बुधवार को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में क्षेत्ररक्षक के तौर पर एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक नौ कैच लेने का कारनाम किया है, वह ऐसा करने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले खिलाड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने अजिंक्या रहाणे के विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।

दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज मारक्रम ने आज यहां बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरान पांच कैच पकड़े। इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने चार कैच लेते हुए अपने कैच की संख्या 9 कर ली। मार्करम से पहले दक्षिण अफ्रीका के लिए एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड बर्ट वोग्लर के नाम था। उनके छह कैच की बराबरी ब्रूस मिशेल ने 1931 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जैक्स कैलिस ने जनवरी 2012 में श्रीलंका के खिलाफ, ग्रीम स्मिथ ने नवंबर-दिसंबर 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डब्ल्यूएसीए (पर्थ) में और डेविड बेडिंघम ने जनवरी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने देश के पांच दिग्गजों को पछाड़ दिया है। टेस्ट सीरीज में भारत का सुपड़ा साफ करने के बाद मारक्रम ने कहा, " यह बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूं तो सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया।

सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में राजस्थान ने तमिलनाडु को हराया

दीपक हुड्डा का नाबाद अर्द्धशतक, कार्तिक शर्मा, शुभम गढ़वाल की आतिशी पारी

जयपुर, 26 नवंबर। सुमित गोदारा का शानदार शतक, करण लाम्बा का नाबाद अर्धशतक, गणेश सुथार, नीलेश टांक, चेतन शर्मा व अमोल चेलानी भी चमके। बीसीसीआई अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी राजस्थान - गुजरात मैच (गुजरात जीती)।

सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी - राजस्थान ने तमिलनाडु को 6 विकेट से हराया। आज अहमदाबाद में खेले गए राजस्थान - तमिलनाडु मैच को राजस्थान ने बड़ी आसानी व 6 विकेट से जीता। तमिलनाडु पारी 169 / 8 टीम के लिए सोनू यादव नाबाद 43, जगदीशन 29 रन

राजस्थान के गेंदबाज अशोक शर्मा व मानव सुथार से शानदार गेंदबाजी करते हुए तमिलनाडु को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। गेंदबाजअशोक शर्मा 40 / 3, मानव सुथार 22 /2 व कमलेश नागरकोठी 33 / 1 विकेट राजस्थान पारी 170/ 4 (16 . 3 ओवर) टीम के लिएदीपक हुड्डा नाबाद 76 (36 गेंद, 6 चोक्के, 6 छक्के), कार्तिक शर्मा 35 (17 गेंद, 1 चौक्का 4 छक्के), शुभम गढ़वाल 32 (22 गेंद, 4 चोक्के, 2 छक्के) व महिपाल लोमरोर 17 रनो का योगदान दिया।

तमिलनाडु के गेंदबाज नटराजन 16 / 2 विकेट। अंडर 23 एक दिवसीय ट्रॉफी (महाराष्ट्र को हरा राजस्थान ने सेमी फाइनल में प्रवेश किया) आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए क्वाटर फाइनल मैच में राजस्थान ने सुमित गोदारा के शतक व करण लाम्बा, अमोल चेलानी, गणेश सुथार, नीलेश टांक व चेतन शर्मा के शानदार प्रदर्शन की सहायता से महाराष्ट्र को हरा प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मेंप्रवेश किया।

महाराष्ट्र पारी 245 आल आउट, टीम के लिए किरण 91, अनिरुद्ध 43 व ऐ पंवार 46 रन। राजस्थान के गेंदबाज गणेश सुथार 32 / 3, नीलेश टांक 53 / 2 व चेतन शर्मा 70 / 2 विकेट। राजस्थान पारी 250 / 5, बल्लेबाज सुमित गोदारा ने शानदार शतकीय पारी खेल टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भुमका दर्ज की, टीम के लिए सुमित गोदारा 109 (121 गेंद, 8 चोक्के व 5 छक्के), करण लाम्बा नाबाद 51, अमोल चेलानी 47 रन।

महाराष्ट्र के गेंदबाज वैभव 57/ 2 विकेट, नडियाद, गुजरात में खेले जा रहे राजस्थान - गुजरात अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी मैच (गुजरात जीती) राजस्थान पहली पारी 245 आल आउट, गुजरात पहली पारी 308 आल आउट, राजस्थान दूसरी पारी 250 आल आउट, गुजरात दूसरी पारी 188/ 3, टीम के लिए मलय नाबाद 77 व कुश नाबाद 36 रन, राजस्थान के गेंदबाज कुशाग्र ओझा 1 विकेट।

ट्रैप शूटर नीरू ढांडा ने लगातार चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गोल्ड जीता, जैन यूनिवर्सिटी पदक तालिका में टॉप पर

चंड़ीगढ़ के हर्ष सरोहा ने पुरुषों की 50 बटरफ्लाई फाइनल में जैन के श्रीहरि नटराज को हराया

जयपुर, 26 नवंबर। ट्रैप शूटर नीरू ढांडा और आदित्य भारद्वाज ने जगतपुर शूटिंग रेंज में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को शॉटगन के चारों मेडल दिलाने में मदद की, जबकि उनके साइकिलिस्ट ने दोनों इंडिविजुअल रोड रेस जीतकर अपने गोल्ड मेडल संख्या को दोबरे अंक में पहुंचा दिया।

केआईयूजी 2025 का पांचवां एडिशन राजस्थान के सात शहरों में हो रहा है। 222 यूनिवर्सिटी के 4448 एथलीट 23 मेडल खेलों में मुकाबला कर रहे हैं। ये गेम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के अंडर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर हो रहे हैं और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी इन्हें होस्ट कर रही है।

नीरू, जो मौजूदा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में लगातार चौथा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता, जिसमें उनका फ़ाइनल स्कोर 47 पॉइंट्स था। साथ ही, उन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को पोडियम पर पूरी तरह से हावी रखा, जिसमें मनीषा कीर (39 पॉइंट्स) और नंदिका सिंह (30) ने क्रमश: सिल्वर और ब्रॉन्ज़ मेडल जीते। तीनों ने 344 पॉइंट्स के स्कोर के साथ टीम गोल्ड भी जीता।

नीरू क्वालिफ़ाइंग में मनीषा के बाद दूसरे स्थान पर रही थीं, लेकिन फ़ाइनल में उन्होंने अपना लेवल ऊपर उठाया। उन्होंने साईमीडिया को बताया, मैंने आज गोल्ड जीतने का पक्का इरादा कर लिया था क्योंकि यह मेरा आखिरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाला है। मैंने यूनिवर्सिटी गेम्स के पिछले तीन एडिशन में गोल्ड जीता था और मैं इसे एक और गोल्ड मेडल के साथ खत्म करना चाहती थी।

नीरू ने पहली बार 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लिया था। तब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और तब से यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका दबदबा रहा है। आदित्य भारद्वाज ने जीएनडीयूकी मेन्स ट्रैप टीम को फाइनल में 45 के स्कोर के साथ

गोल्डन डबल दिलाया। पंजाबी यूनिवर्सिटी के जंगशेर सिंह विर्क ने 43 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि मानव रचना के भक्तियार मलिक ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। इससे पहले दिन में, साइकिलिस्ट मीनाक्षीरोहिल्ला ने इंडिविजुअल रोड रेस में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी इंडिविजुअल टाइम ट्रायल जीत में और इजाफा किया और उनकी टीम के साथी अक्षर त्यागी ने पुरुष कैटेगरी का खिताब जीतकर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल की संख्या 10 कर दी।

दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की चैंपियन जैन यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को अपने आठ तैराकी गोल्ड मेडल में चार और गोल्ड मेडल जोड़कर तालिका में टॉप पर अपनी जगह बनाए रखी। उन्होंने 4100 फ्रीस्टाइल रिले और नीना वेंकटेश (महिलाओं की 50मीबटरफ्लाई) और भव्या सचदेवा (महिलाओं की 400मी आईएम) दोनों में

जीत हासिल की और स्विमिंग पूल में दो और गोल्ड मेडल जीते।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हर्ष सरोहा ने पुरुषों की 50मीबटरफ्लाई में ओलंपियन श्रीहरि नटराज को हराकर 24.90एसके समय के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 200मीबटरफ्लाई में भी 2:06.88 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता और उनके टीममेट ईशान राठी ने 200मीबैकस्ट्रोक रेस में 2:13.51एस के समय के साथ जीत हासिल की।

परिणाम : बैडमिंटन (क्वार्टर फ़ाइनल्स)

पुरुष : महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम ने श्री जेजेटी विश्वविद्यालय, झुंझुनू को 3-1 से हराया। चितकारा विश्वविद्यालय ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को 3-2 से हराया। पंजाब विश्वविद्यालय ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को 3-1 से हराया। मुंबई विश्वविद्यालय ने एसआरएम विश्वविद्यालय को 3-2 से हराया।

महिला : चितकारा विश्वविद्यालय ने श्री जेजेटी विश्वविद्यालय, झुंझुनू को 2-0 से हराया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय को 2-0 से मात दी। एसआरएम विश्वविद्यालय ने केआईआईटी को 2-0 से हराया। महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक ने जैन विश्वविद्यालय को 2-1 से हराया।

साइक्लिंग महिला - व्यक्तिगत रोड रेस:
स्वर्ण - मीनाक्षी (जीएनडीयू)
रजत - मुस्कान गुप्ता (वीर नरमद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय)
कांस्य - हेमलता धाकड़ (बागलकोट विश्वविद्यालय)

पुरुष - इंडिविजुअल रोड रेस:
स्वर्ण - अक्षर त्यागी (जीएनडीयू)

रजत - अद्वैत शंकर एसएस (केरल विश्वविद्यालय)
कांस्य - चिराग सहगल (एलपीयू)

फुटबॉल (ग्रुप चरण)

पुरुष : आदमस विश्वविद्यालय ने छत्रपति एसएम विश्वविद्यालय को 3-1 से हराया। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1-1 से ड्रॉ खेला।

शूटिंग महिला - ट्रैप :
स्वर्ण - नीरू (जीएनडीयू) 47
रजत - मनीषा कीर (जीएनडीयू) 39
कांस्य - नंदिका (जीएनडीयू) 30

महिला - ट्रैप टीम :
स्वर्ण - गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 344
रजत - पंजाब विश्वविद्यालय 298

पुरुष - ट्रैप :
स्वर्ण - आदित्य भारद्वाज (जीएनडीयू) 45
रजत - जंगशेर सिंह विरक (पीबीआई) 43
कांस्य - भक्तियार मलिक (एमआरएस) 34

पुरुष - ट्रैप टीम :
स्वर्ण - गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 335
रजत - जामिया मिलिया इस्लामिया 291
कांस्य - स्वामी विवेकानंद एस विवि.103

स्विमिंग महिला : 400 मी आईएम: भाव्या सचदेवा (जैन विश्वविद्यालय) 5:27.72 - स्वर्ण
200 मी बैकस्ट्रोक: प्रत्यासा रॉय (उत्कल विश्वविद्यालय) 2:29.51 - स्वर्ण
50 मीब्रेस्टस्ट्रोक: ऋत्विका एम (केआईआईटी) 34.95 - स्वर्ण
50 मीबटरफ्लाई: नीना वेंकटेश (जैन विश्वविद्यालय) 28.40 - स्वर्ण
4100 मीफ्रीस्टाइल रिले: जैन विश्वविद्यालय 4:12.50 - स्वर्ण

पुरुष: 1500 मीफ्रीस्टाइल: अनीश गौड़ा (क्राइस्ट विश्वविद्यालय) 16:37.66 - स्वर्ण
200 मीबटरफ्लाई: हर्ष सरोहा (चंडीगढ़ विश्वविद्यालय) 2:06.88 - स्वर्ण
200 मीबैकस्ट्रोक: ईशान राठी (चंडीगढ़ विश्वविद्यालय) 2:13.51 - स्वर्ण
50 मीब्रेस्टस्ट्रोक: विदिथ शंकर (रेवा विश्वविद्यालय) 29.28 - स्वर्ण
50 मीबटरफ्लाई: हर्ष सरोहा (चंडीगढ़ विश्वविद्यालय) 24.90 - स्वर्ण
4100 मीफ्रीस्टाइल रिले: जैन विश्वविद्यालय 3:37.15 - स्वर्ण

वेटलिफ्टिंग महिला 58 किग्रा :
स्वर्ण - रिमा भोई (एलपीयू) 197 किग्रा
रजत - राज्यश्री बिस्वास (एडीयू) 195
कांस्य - खुशी कुमारी (पीपीयू) 183

पुरुष : 65 किग्रा: स्वर्ण - संजय लोखंडे (एसपीपीयू) 244 किग्रा
71 किग्रा: स्वर्ण - आरएस तरुण शर्मा (जीकेयू) 260 किग्रा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर एवं उदयपुर संभाग के भाजपा जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ उपस्थित थे।

सभी कार्यकर्ता निकाय व पंचायतीराज चुनावों की तैयारी करें- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर व भरतपुर संभाग के पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि सभी जिलाध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष जनसेवा के साथ समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए काम करें।**
- **बैठक में मुख्यमंत्री के साथ भरत राठौड़, प्रेम चन्द बैरवा, अरूण चतुर्वेदी, घनश्याम तिवाड़ी, अशोक परनामी व राजेन्द्र राठौड़ भी शामिल हुए।**

जयपुर, 26 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर एवं उदयपुर संभाग के भाजपा जिला अध्यक्षों एवं मंडल अध्यक्षों तथा कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा में मेहनती और निष्ठावान कार्यकर्ता संगठन से लेकर समाज व देश की सेवा में तत्पर रहता है, जिससे वह सदैव आगे बढ़ता है तथा सम्मान भी प्राप्त करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है तथा प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए पार्टी का कार्य सर्वोपरि है, इसलिए दिए गए दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएं तथा मंडल स्तर की नियमित बैठकें भी करें। उन्होंने कहा कि मेहनती कार्यकर्ता और पदाधिकारी राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और 2 वर्षों की उपलब्धियों को सोशल मीडिया एवं अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आमजन तक पहुंचाएं। वे पार्टी की रीति और नीति को भी हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जनसेवा के साथ-साथ समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कार्य करें। संगठन में युवाओं को केन्द्र व राज्य के कार्यक्रमों से जोड़ें और उन्हें जिम्मेदारी भी दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने भेद-भाव और तुष्टीकरण के आधार पर वार्डों और पंचायतों को जोड़ा और तोड़ा था, लेकिन हमारी सरकार ने तथ्यों और आवश्यकता को देखते हुए पुनर्गठन के कार्य को पूरा किया है, इसलिए सभी कार्यकर्ता आने वाले निकाय और पंचायतीराज चुनाव की तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में नए लोगों को पार्टी से जोड़ें तथा उन्हें जिम्मेदारी दें। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को काम के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से आयोजित संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया।

मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत का यह पहला सार्वजनिक संबोधन था। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश ने संविधान दिवस को एक उत्साहवर्धक अवसर बताया और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में बार की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अधिवक्ताओं को संवैधानिक आदर्शों के मशाल-वाहक बताते हुए कहा कि बार की गहरी विद्वत्ता संवैधानिक व्याख्या की नींव बनाती है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कानूनी दिग्गजों जैसे नानी पालकीवाला, एम.सी. सीतलवाड, संविधान निर्माताओं डॉ. बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के योगदान को याद किया और कहा कि भारत की कानूनी यात्रा उन अधिवक्ताओं द्वारा आकार दी गई है जिनकी बुद्धि और ईमानदारी ने राष्ट्र के विकास का मार्गदर्शन किया।

सीबीआई ने आईटीएटी सदस्य, एडवोकेट व अपीलकर्ता को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

सीबीआई के छापों में एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि बरामद हुई है

- **आयकर अपील ट्रिब्यूनल की न्यायिक सदस्य डॉ. सीता लक्ष्मी की सरकारी कार से 30 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी बरामद हुई। सीबीआई ने जाँच का दायरा बढ़ाकर जयपुर, कोटा व अन्य शहरों में आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे।**

जयपुर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जयपुर में कार्रवाई करते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की न्यायिक सदस्य, एक वरिष्ठ वकील को गिरफ्तार किया है। अधिकरण में अपील करने वाले शख्स को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई उस आपराधिक नेटवर्क पर की गई है जो कथित तौर पर लंबित टैक्स अपीलों को घूस लेकर सेट कर रहा था।

सीबीआई के सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले में एक एडवोकेट राजेंद्र सिसोदिया,आईटीएटी की न्यायिक सदस्य डॉ. एस. सीता लक्ष्मी, एक सहायक रजिस्ट्रार और अन्य अज्ञात सरकारी व निजी व्यक्तियों के शामिल होने का खुलासा हुआ है। यह पूरा गिरोह अपीलकर्ताओं के पक्ष में फैसले दिलवाने के लिए रिश्वत ले रहा था।

सीबीआई ने 25 नवंबर 2025 को इस संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके साथ ही आईटीएटी के एक एडवोकेट राजेंद्र सिसोदिया को 5.50 लाख रुपये की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। यह रिश्वत कथित तौर पर अपीलकर्ता ने हवाला नेटवर्क के माध्यम से दी थी। इसी कड़ी में ऑपरेशन के अगले ही दिन बुधवार को आईटीएटी जयपुर की न्यायिक सदस्य डॉ. एस. सीता लक्ष्मी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी सरकारी कार से 30 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद हुई। रिश्वत देने वाले अपीलकर्ता मुजम्मल को भी बुधवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए जयपुर, कोटा व अन्य शहरों में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की। जिसमें एक करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। इसके साथ ही संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य संदिग्ध दस्तावेज भी सीबीआई के हाथ लगे हैं। जो इस खेल में संगठित सिंडिकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सीबीआई ने तीन दिन के रिमांड पर लिया है। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इस गिरोह में उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी शामिल थे। जो न्यायिक प्रक्रिया को पैसे के दम पर रौंदने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में सीबीआई की जांच और अग्रिम अनुसंधान जारी है।

दिल्ली विस्फोट : जांच एजेन्सियों ने डॉ. आदिल की डिलीट चैट वापस हासिल की

फोन संदेशों में आदिल बार-बार पैसों की मांग कर रहा है

- **सूत्रों के अनुसार 5,6,7, और 9 दिसम्बर 2025 के संदेशों में तत्काल पैसों की आवश्यकता बताई गई। अनुमान है कि यही पैसा हमले में खर्च हुआ।**

नयी दिल्ली, 26 नवम्बर। दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले में जांच एजेंसियों ने बुधवार को दावा किया कि उन्हें डॉ. आदिल के डिलीट किए गए व्हाटसअप चैट को दोबारा हासिल करने में सफलता मिल गयी है।

इस मामले में डा. आदिल एक मुख्य आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी से फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का पता चला है।

जांच एजेंसियों को दोबारा मिले इन संदेशों में उसकी आर्थिक तंगी की स्थिति स्पष्ट दिखती है। वह बार-बार पैसों की मांग करता दिखाई देता है। जांचकर्ताओं का संदेह है कि यही रकम उस हमले में इस्तेमाल हुई, जिसमें आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी ने अपनी आई20 कार में विस्फोट कर दिया था। इस हमले में पंद्रह लोगों की जान गयी थी और बत्तीस से अधिक लोग घायल हुए थे।

एक सूत्र ने बताया, आदिल के फोन से सभी संदेश मिटा दिए गए थे। इन संदेशों में वह लगातार पैसों की मांग करता दिखाई देता है। यहां तक कि उसने एक बार तो अपनी तनख्वाह तक एडवांस में मांगी।

संदेशों के जरिए हुई बातचीत 5, 6, 7 और 9 सितम्बर 2025 की हैं। इनमें उसने तत्काल पैसों की आवश्यकता बताई है। जांच एजेंसियों का अनुमान है कि यही पैसा हमले में खर्च हुआ।

सूत्रों के अनुसार, कुल 26 लाख रुपये में से 8 लाख रुपये आदिल ने उपलब्ध कराए थे। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि समूह में आदिल को खजांची कहा जाता था।

जांच में यह भी पुष्टि हुई है कि डॉ. आदिल कथित घटनाओं से ठीक पहले श्रीनगर से 11 अक्टूबर को दिल्ली आया था।

राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 17 साल पहले 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान-समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने हमला किया था। चार दिन तक चले इस हमले में 166 लोगों ने जान गंवाई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

इस हमले में मुंबई के लग्जरी होटल, प्रमुख रेलवे स्टेशन और एक यहूदी सांस्कृतिक केन्द्र को निशाना बनाया गया था। हमले के लिए आतंकवादी समुद्र के रास्ते आये थे। उन्होंने कई गुटों में बंटकर गाड़ियों पर कब्ज़ा किया। इसके बाद उन्होंने ताज महल पैलेस, ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नरीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल, मेट्रो सिनेमा और लियोपोल्ड कैफ़े सहित, कई प्रमुख जगहों को निशाना बनाया।

कसाब को 2010 में मौत की सज़ा सुनायी गयी और 2012 में पुणे के एक कारागार में उसे फांसी दी गयी।

राबड़ी देवी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तेजस्वी से उस बँगले को खाली करने के लिए कह दिया गया। तेजस्वी ने इस निर्णय/आदेश को अदालत में चुनौती दी, मगर 19 फरवरी 2019 के पटना हाई कोर्ट के फैसले में उनके खिलाफ निर्णय आया और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वे सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से बँगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ की सुविधाएँ वापस ले ली जायें। इस फैसले का असर राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी और जगन्नाथ मिश्र पर भी पड़ा, लेकिन राबड़ी देवी के पास 10, सर्कुलर रोड वाला बँगला इसलिए बना रहा, क्योंकि वे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थीं। आज भी वे उसी पद पर हैं, लेकिन नई सरकार का अब इस बँगले को लेकर अलग रुख है। यह बँगला प्रकरण इस बात का संकेत है कि नई नीतीश सरकार लालू परिवार से जुड़े लंबित केसों में नरमी नहीं बरतेगी।

'जब अलावेरु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेनी चाहिए और जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

आलावेरू और उनकी टीम का कहना है कि वे अगले चुनाव के लिए नई पीढ़ी की टीम तैयार कर रहे थे, जो आगामी चुनाव में दिखेगी। लेकिन इस लाइन को कुछ ही लोग मान रहे हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं के पास उनके कामकाजी तरीके के खिलाफ शिकायतों की लम्बी लिस्ट है। एक और गुट का कहना है कि अगर पार्टी को आगे बढ़ना है, तो उसे राजद (आरजेडी) के सहारे को छोड़कर अपनी मजबूती से खुद खड़ा होना होगा और खुद को फिर से बनाना होगा।आरजेडी के खिलाफ भी कई गंभीर शिकायतें हैं, जैसे कि कांग्रेस को हारने वाली सीटें दी गईं और पार्टी को हराने के लिए विभिन्न चालें चलीं गईं। साथ ही, दोस्ताना मुकाबलों में कांग्रेस ने बुरी तरह से खराब प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने केवल 5 सीटों पर ही जमानत गंवाई, जहाँ वह आरजेडी के साथ दोस्ताना मुकाबले में थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन वहाँ हार गया।

अगर पार्टी के नेता खुले तौर पर और ईमानदारी से बोलते हैं और उन्हें चुप कराने की कोशिश नहीं की जाती, तो पार्टी को इससे फायदा हो सकता है।

नहीं तो पार्टी के लिए समस्याओं का अंबार लग सकता है।

मुंबई की मतदाता सूचि में बड़ी अनियमितताएं सामने आईं

मुंबई, 26 नवम्बर। मुंबई में आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ सामने आने के बाद, प्रशासन ने इन्हें ठीक करने का फैसला किया है।

अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सबसे बड़ी दिक्कत मतदाता सूची में नामों के दो-दो बार दर्ज होने की सामने आई है। इन डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करना

- **प्रशासन मुंबई के नगर निकाय चुनावों से पहले इन कमियों को दूर करने में जुटा है**

और उनको सूची से हटाना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए पांच दिसंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद मतदाता सूची को ठीक करना और गलत एंट्री हटाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने स्वीकार किया कि बृहन्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने डुप्लीकेट नामों का मुद्दा उठाया और इसे "गंभीर मामला" बताते हुए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मुद्दे ने मुंबई में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, मनसे, राकांपा (शरद पवार), कांग्रेस, किसान-कामगार पार्टी, वाम दलों तथा अन्य विपक्षी समूहों ने मतदाता सूची में कथित हेरफेर और "वोट चोरी" का आरोप लगाते हुए शहर में ट्रुथ मार्च निकाला। विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। इस बीच, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने धारावी की मतदाता सूची में अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया।

भारतीय संविधान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को उनकी अपनी भाषा में संविधान को पढ़ने और समझने का मौका है। आप अपने संविधान को अपनी भाषा में पढ़ सकते है। सरकार ने 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं में अनुवाद कराया है- नेपाली, मलयालम, मराठी, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओड़िया, असमिया। इन अनुवादों को केन्द्रीय विधि मंत्रालय के विधायी विभाग ने तैयार किया है।

अधिकारियों के अनुसार, इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि नेपाली भाषा में संविधान का उपलब्ध होना है। यह कदम भारत और नेपाल के बीच के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संबंधों को देखते हुए काफी अहम है। नेपाली भाषी नागरिक अब अपनी भाषा में भारतीय संविधान को पढ़ और समझ सकेंगे, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और जुड़ाव और मजबूत होगा।

विद्याधर नगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया, खो-नागोरियान सहित, जयपुर के लगभग हर हिस्से में पिछले कुछ महीनों से लैपर्ड की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। आबादी क्षेत्र और हाई-सिक्यूरिटी ज़ोन में लैपर्ड का मूवमेंट वन विभाग और पुलिस दोनों के लिए चुनौती बन गया है।

ट्रंप की लाज बचाने के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। प्रस्तावित समझौते की पूरी शर्तें अभी सामने नहीं आई हैं और सबसे अहम बात, रूस ने सार्वजनिक रुप से अभी तक किसी फ्रेमवर्क को मंजूरी नहीं दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के सतर्क बयान, जिसमें उन्होंने अमेरिकी पहल को स्वीकार तो किया लेकिन रूस की स्थिति स्पष्ट नहीं की, यह बात हालात की नज़ाकत को स्पष्ट करती है। अगर रूस ने खुलकर सहमति नहीं दी, तो ट्रम्प पर अधूरी कूटनीति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लग सकता है। ऐसी स्थिति उनके लिए उल्टी भी पड़ सकती है और आलोचनाएं और तेज़ हो सकती हैं।

फिर भी, ट्रम्प प्रशासन को विश्वास है कि बातचीत में बनी गति घरेलू राजनीति की धार बदल सकती है। खबर है कि अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल रूस के अधिकारियों से अबू धाबी में बातचीत कर रहे हैं, ताकि मॉस्को की सहमति सुनिश्चित की जा सके। वाइट हाउस भी संकेत दे रहा है कि ऐतिहासिक समझौता होने वाला है। अगर ट्रम्प खुद को इस शांति प्रयास का सूत्रधार साबित कर पाए, या कम से कम वे ऐसे राष्ट्रपति साबित हुये, जिन्होंने सभी पक्षों को फिर से बातचीत की मेज़ पर बैठाया, तो इससे विरोधियों की आलोचना कम हो सकती है और हाल के हफ्तों में कमजोर हुई उनकी राजनीतिक स्थिति फिर मज़बूत हो सकती है।

डेमोक्रेट अभी भी सावधान और संदेहपूर्ण हैं। उनका कहना है कि इस प्रशासन के कई विदेश नीति प्रयासों ने बड़े-बड़े दावे तो किए, लेकिन स्थायी परिणाम नहीं दिए। यूरोपीय सहयोगियों को भी चिंता है कि अमेरिका तेज़ प्रगति के चक्कर में दीर्घकालीन क्षेत्रीय स्थिरता की उपेक्षा कर रहा है। हालांकि आलोचक भी मानते हैं कि यदि शांति समझौता वास्तव में सफल होता है, तो इसका राजनीतिक प्रभाव बेहद बड़ा होगा।

फिलहाल, अभी तो ट्रम्प की प्रैसिडैंसी की कमज़ोरियाँ साफ दिखाई दे रही हैं, गिरते सर्वेक्षण, कांग्रेस की बेचैनी और जनता की बढ़ती नाखुशी। लेकिन यूक्रेन शांति पहल ने महीनों बाद उन्हें पहला मजबूत मौका दिया है, जिससे उन्हें अपनी नेतृत्व छवि को दोबारा गढ़ने का एक मौका मिल सकता है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है और रूस भी इसमें शामिल होता है, तो राष्ट्रपति ट्रम्प फिर से राजनीतिक गति पा सकते हैं। लेकिन अगर बातचीत अटक गई, तो उनकी कूटनीतिक महत्वाकांक्षा और वास्तविकता के बीच का अंतर उनकी राजनीतिक मुश्किलों को और बढ़ा सकता है।

आने वाले कुछ सप्ताह, पूर्वी यूरोप में भी और अमेरिकी राजनीति में भी, तय करेंगे कि ट्रम्प की यह शांति पहल एक ऐतिहासिक उपलब्धि बनती है या एक और ऐसी खबर, जो उनके डगमगाते कार्यकाल में थोड़ी देर चर्चा के बाद गायब हो जाती है।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार बम धमाके करने वाले उमर के छह और खास साथियों को गिरफ्तार किया है।

एजेंसी इस आत्मघाती धमाके के सिलसिले में अलग-अलग सुरागों की जांच कर रही है। इस भयानक हमले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए संबंधित पुलिस के साथ मिलकर कई राज्यों में एनआईए अधिकारी तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस आतंकी हमले के पीछे की पूरी साज़िश का पता लगाने की एनआईए कोशिशें जारी हैं।

बिहार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यदि यह गतिरोध जारी रहता है, तो स्पीकर का चुनाव, जो सामान्यत: एक रूटीन प्रक्रिया होती है, नई सरकार के लिए पहला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। फिलहाल, सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या दोनों गठबंधन पार्टियां 1 दिसम्बर को विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले इस बढ़ती जा रही दरार को पाटने में सफल हो पाएंगी।

'बाहरी बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी'

आईएमएफ ने भारतीय आर्थिक वृद्धि की तारीफ की और अनुशासन बनाये रखने की सलाह दी

- **आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाये गये 50 प्रतिशत आयात शुल्क का प्रभाव घरेलू उपभोग बढ़ने के कारण कम होगा।**

वाशिंगटन, 26 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने एक बार फिर भारत की आर्थिक वृद्धि की तारीफ करते हुए बुधवार को कहा कि बाहरी बाधाओं के बावजूद यह मजबूत बनी रहेगी, हालांकि उसने करों में कटौती को लेकर वित्तीय अनुशासन बनाये रखने की भी सलाह दी है।

आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के भारतीय अधिकारियों के साथ मशविरे के बाद जारी स्टाफ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर 6.5 प्रतिशत और 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में 7.8 प्रतिशत रही है। उसने कहा कि खाने-पीने की चीजों की महंगाई कम होने से मुद्रास्फीति की दर में भारी गिरावट आयी है। वित्तीय और कॉर्पोरेट सेक्टर मजबूत बने हुए हैं, वित्तीय अनुशासन बेहतर हुआ है और चालू खाते का घाटा कम हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी बाधाओं के बावजूद, अनुकूल घरेलू कारकों की वजह से वृद्धि दर मजबूत बनी रहेगी और अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क का प्रभाव घरेलू उपभोग बढ़ने की वजह से कम होगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में हालांकि कटौती और आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के मद्देनजर आईएमएफ ने वित्तीय अनुशासन बनाये रखने की जरूरत पर बल दिया है।

कार्यकारी निदेशकों ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर जीएसटी और व्यक्तिगत आयकर में कटौती के प्रभाव पर नजदीकी नजर रखने की सलाह दी है।

उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिकी आयात शुल्क के मद्देनजर निर्यातकों को दी गयी राहत लक्षित, पारदर्शी और सीमित समय के लिए होनी चाहिये। मध्यम अवधि में उन्होंने घरेलू राजस्व बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, विकसित अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में उच्च विकास संभावना वाले वृहत ढांचागत सुधारों को बढ़ावा देना मददगार हो सकता है।

'अनियंत्रित ऑन लाइन गेमिंग ऐप आतंकवाद को फंड करते हैं'

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में दाखिल हलफनामे में यह खुलासा किया

- **हलफनामे में भी यह भी कहा गया है कि विज्ञापनों, सैलिब्रिटी और सोशल इन्फ्लुएंसर के प्रचार से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म युवाओं और कमजोर तबकों में तेजी से फैल रहा है।**

नई दिल्ला, 26 नवम्बर। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिना नियमन वाले ऑनलाइन गेमिंग एप्स का संबंध आतंकवाद को वित्तीय मदद देने और धन शोधन से जुड़ा है। इसलिए इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए कानून लाना जरूरी था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि वे इस मामले की कल यानी गुरुवार को सुनवाई करने का प्रयास करेंगे।

सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि बिना रोक-टोक के बढ़ रहे ऑनलाइन जुए वाले गेम्स का संबंध वित्तीय धोखाधड़ी, धनशोधन, कर (टैक्स) चोरी और कई मामलों में आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने से भी जुड़ा है। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर विज्ञापनों, सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के प्रचार से युवाओं और कमजोर तबकों तक तेजी से पहुंच रहे हैं, जिससे उनका प्रभाव बढ़ रहा है। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन जुए वाले गेम्स का व्यक्तियों, परिवारों, समाज और पूरे देश पर बुरा असर पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, एल्गोरिदम और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जैसे तकनीकी पहलुओं के चलते, ये कंपनियां विदेशों से संचालित होती हैं, घरेलू और राज्य स्तर के कानूनों को नजरअंदाज करती हैं और इन्हें रोकना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से 2025 का ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन कानून बनाया गया।

सरकार ने कहा कि जनता की भलाई के लिए यह जरूरी था कि केन्द्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी ले और एक सुरक्षित, व्यवस्थित और नवाचार को बढ़ावा देने वाला डिजिटल माहौल तैयार करे।

'कर्नाटक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाले हैं। यह सत्ता-संघर्ष कर्नाटक इकाई में गुटबाजी की गहरी जड़ों को उजागर करता है, जहां एक समूह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का समर्थन कर रहा है और दूसरा डीकेएस को सत्ता सौंपने की मांग करता है।

आज दोपहर की यह स्वीकारोक्ति पिछले हफ्ते की उस टिप्पणी से एक यू-टर्न भी है, जिसमें पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने, जून की तरह ही, यह कहा था कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908